बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु ऐतिहासिक पहल...

शेखावाटी मिशन-100

राजनीति विज्ञान

कक्षा – 12

कार्यालय : संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू (राज.)
प्रभारी : शैक्षिक प्रकोष्ठ अनुभाग, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, सीकर

: missionshekhawati100@gmail.com | 9413361111, 9828336296

टीम शेखावाटी मिशन-100

घनश्यामदत्त जाट
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
झुन्झुनू-सीकर (राज.)

रमेशचन्द्र पूनियां
जिला शिक्षा अधिकारी
चूरू (राज.)

लालचन्द नहलिया
जिला शिक्षा अधिकारी मा.
सीकर (राज.)

अमर सिंह पचार
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
झुन्झुनू (राज.)

रिछपाल सिंह मील
अति. जिला परि. समन्वयक
समग्र शिक्षा, सीकर (राज.)

महेन्द्र सिंह बड़सरा
सहायक निदेशक
कार्यालय संयुक्त निदेशक, चूरू

हरदयाल सिंह फगेड़िया
प्रभारी शेखावाटी मिशन-100
अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
सीकर (राज.)

रामचन्द्र सिंह बगड़िया
अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
सीकर (राज.)

नीरज सिहाग
अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
झुन्झुनू (राज.)

सांवरमल गहनोलिया
अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
चूरू (राज.)

महेश सेवदा
संयोजक शेखावाटी मिशन-100
सीकर (राज.)

रामावतार भदाला
सहसंयोजक शेखावाटी मिशन-100
सीकर (राज.)

तकीनीकी सहयोग

राजीव कुमार, निजी सहायक | पवन ढाका, कनिष्ठ सहायक | महेन्द्र सिंह कोक, सहा. प्रशा. अधिकारी | अभिषेक चौधरी, कनिष्ठ सहायक

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), सीकर

शैक्षिक प्रकोष्ठ अनुभाग, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, सीकर

माननीय शिक्षा मंत्री की कलम से.....

!! शुभकामना संदेश !!

सम्मानित शिक्षक साथियों,

हम सभी के लिए यह गौरव का विषय है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नित नये आयाम छू रहा है। नीति आयोग के नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) 2020 में राजस्थान सम्पूर्ण भारत में तीसरे स्थान पर रहा है। इस वर्ष राजस्थान, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में 8027 बाल वैज्ञानिकों के चयन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा हैं। इसी परम्परा व सोच को निरन्तर बनाए रखने के प्रयास में इस वर्ष शेखावाटी मिशन–100 का क्रियान्वयन संयुक्त निदेशक परिक्षेत्र चूरु के अधीन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर द्वारा किया जा रहा है। अनुभवी तथा ऊर्जावान विषय विशेषज्ञों की लगन व अथक मेहनत से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी संशोधित पाठ्यक्रम व मॉडल पेपर के आधार पर विषयवस्तु व मॉडल पेपर तैयार किये गये हैं, जिनको बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा रहा है।

मैं इस मिशन प्रभारी सहित सभी विषयाध्यापकों की कर्मठ टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपनी समर्पित कार्यशैली से इस नवाचारी कार्य को अंजाम दिया है। मेरा सभी संस्थाप्रधानों से आग्रह है कि वे सभी विषयाध्यापकों से समन्वय कर इस परीक्षोपयोगी सामग्री को विद्यार्थियों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रयास पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक नवाचार साबित होगा एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित।

3/3/21

गोविन्द सिंह डोटासरा
शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
राजस्थान सरकार, जयपुर

निदेशक महोदय की कलम से.....

!! शुभकामना संदेश !!

सम्मानित शिक्षक साथियों,

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु के नेतृत्व में 'शेखावाटी मिशन–100' के तहत माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा में उपयोगी विषयवस्तु एवं प्रश्नकोश तैयार किया जा रहा है हालांकि यह सत्र कोविड–19 के कारण प्रभावित रहा है इसमें विद्यार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

'शेखावाटी मिशन–100' की टीम ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार नवाचार करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों के लिए जो विषयवस्तु व प्रश्नकोश निर्माण किया है आशा करते है कि यह विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होगा।

प्रतिभाशाली और कर्मठ ऊर्जावान शेखावाटी मिशन–100 की टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ।

शुभकामनाओं सहित।

सौरभ स्वामी (IAS)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

संयुक्त निदेशक की कलम से.....

!! शुभकामना संदेश !!

सम्मानित शिक्षक साथियों,

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु एक शैक्षिक नवाचार के रूप में 2017–18 में शेखावाटी मिशन–100 शुरु किया गया था। इस वर्ष शेखावाटी मिशन–100 की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरु संभाग के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सीकर को मिली है। इस नवाचारी पहल ने पिछले 03 वर्षो में चूरु संभाग में बोर्ड परीक्षा परिणाम में सफलता के नये आयाम बनाये हैं।

पिछले वर्षो में मिली इस अभूतपूर्व सफलता से अभिप्रेरित होकर इस वर्ष शेखावाटी मिशन–100 का दायरा बढ़ाकर 17 विषयों तक किया गया है। इस वर्ष कक्षा–10 के 07 विषयों (संस्कृत व उर्दू सहित) तथा कक्षा 12 में 10 विषयों, जिनमें अनिवार्य हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा विज्ञान संकाय में 04 विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित) तथा कला संकाय में 04 विषयों (हिन्दी, साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास व भूगोल) के लिए बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम व मॉडल पेपर के आधार पर अध्ययन सामग्री व मॉडल पेपर तैयार किये गये हैं। पाठ्य विषय वस्तु को इस प्रकार तैयार किया गया है कि सभी तरह के बौद्धिक स्तर वाले विद्यार्थी कम समय में भी अधिकतम अंक अर्जित कर सकेंगे।

शेखावाटी मिशन–100 में उन विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया है जिनके पिछले वर्षो में अपने विषयों के गुणात्मक रूप से शानदार परीक्षा परिणाम रहे हैं।

मैं इस मिशन को सफल बनाने में सहयोग के लिए संभाग के सभी शिक्षा अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

लालचन्द बलाई
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू

शेखावाटी मिशन-100

बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम सत्र : 2020–21
उच्च माध्यमिक परीक्षा – 2021

विषय : राजनीति विज्ञान

सर्वश्रेष्ठ सफलता सुनिश्चित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ संकलन

हरदयाल सिंह फगेड़िया
प्रभारी शेखावाटी मिशन–100
अति. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
सीकर (राज.)

रवि कुमार निठारवाल
संयोजक राजनीति विज्ञान
रा.उ.मा.वि., खीरवा (सीकर)
मो. : 9772304039

देवी सिंह
सहसंयोजक राजनीति विज्ञान
रा.उ.मा.वि., पीथलपुर (सीकर)

जगदीश प्रसाद बगड़िया
महात्मा गांधी रा.उ.मा.वि., दांता (सीकर)

नेकीराम
रा.उ.मा.वि., बलोद बड़ी (सीकर)

संदीप जड़िया
रा.उ.मा.वि., राजगढ़ (चूरू)

शैक्षिक प्रकोष्ठ अनुभाग, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, सीकर

संदेश

प्रिय विद्यार्थियों !

इस सत्र में बोर्ड परीक्षाएं 6 मई 2021 से आयोजित होने वाली हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम विद्यार्थी के भविष्य की दशा एवं दिशा निर्धारित करता है। इसलिए विद्यार्थी व अभिभावक का तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है और यह चिन्ता इस वर्ष कोविड–19 महामारी ने और बढ़ा दी। प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु अपनी तरफ से वर्षभर कक्षा शिक्षण, गृहकार्य व नोट्स तैयार कर तैयारी करता है परंतु गत वर्ष से कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी के चलते कक्षा शिक्षण कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ है। परीक्षा से पूर्व का समय बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इस महामारी एवं अध्यापन कार्य के प्रभावित होने के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर ने विद्यार्थी हित को देखते हुए लगभग 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किया है जो कि अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के पास सर्वोत्तम सुअवसर है।

अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाकर तैयारी करना आवश्यक होता है। शेखावाटी मिशन–100 राजनीति विज्ञान की टीम द्वारा कम समय में यह पाठ्य सामग्री तैयार की गई है। हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस पाठ्य सामग्री को पढ़कर आपको सफलता मिलेगी। बोर्ड परीक्षा परिणाम में संख्यात्मक व गुणात्मक सुधार के लिए यह एक प्रयास है। प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में परीक्षा की तैयारी हेतु उपयोगी जानकारी व महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा सुझाव है कि आप इस पाठ्य सामग्री को मन लगाकर पढ़ें और अपनी परीक्षा की रणनीति तैयार करें। फिलहाल स्वाध्याय के लिए यह मौसम अनुकूल समय है। आप इसका सदुपयोग करें। देखने में आता है कि अधिकतर विद्यार्थी राजनीति विज्ञान विषय के प्रति गंभीर नहीं होते। अतः अन्य विषयों में विशेष योग्यता अर्जित करने के बावजूद भी राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः सरल विषय मानकर राजनीति विज्ञान विषय की उपेक्षा न करें।

शुभकामनाओं सहित।

खंड–अ
इकाई–1
प्रमुख अवधारणाऐं
न्याय

अति लघूतरात्मक प्रश्न – 1

1 प्लेटो ने मानवीय आत्मा के कितने तत्व बताये हैं ?

उत्तर– 1 बुद्धि 2 शौर्य 3 तृष्णा

2 प्लेटो आत्मा के मानवीय सद्गुण को कौनसा न्याय मानता है ?

उत्तर– व्यक्तिगत न्याय

3 प्लेटो न्याय के कितने रुप मानता हैं ?

उत्तर– 1 व्यक्तिगत न्याय 2 सामाजिक न्याय

4 प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है ?

उत्तर– प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दुसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ।

5 प्लेटो ने न्याय सिद्धान्त की व्याख्या किस पुस्तक में की है ?

उत्तर– रिपब्लिक

6 अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताये हैं ?

उत्तर– 1 वितरणात्मक न्याय 2 सुधारात्मक न्याय

7 मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन थे ?

उत्तर– 1 सन्त ऑगस्टाइन 2 थॉमस एक्विनास

8 अज्ञानता के पर्दे का सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया ?

उत्तर– जॉन रॉल्स

9 उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन थे ?

उत्तर– जैरेमी बेंथम

10 आर्थिक विषमता की बात किस विचारक ने कहीं है ?

उत्तर– कार्ल मार्क्स

अति लघूतरात्मक प्रश्न –2

1 न्याय के भारतीय प्रतिपादकों के नाम लिखिए।

उत्तर– न्याय के भारतीय प्रतिपादकों में मनु, कौटिल्य, शुक्र, भारद्वाज, सोमदेव, विदुर, बृहस्पति आदि।

2 राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के दो साधनों के नाम लिखिए।

उत्तर– राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के व्यस्क मताधिकार, विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है।

3 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख ' को न्याय का मूलमंत्र किसने माना है ?

उत्तर– 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख ' को न्याय का मूलमंत्र जैरेमी बेंथम ने माना है।

4 जॉन रॉल्स ने अपनी किस पुस्तक में आधुनिक परिपेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है ?

उत्तर– जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ''ए थ्यॉरी ऑफ जस्टिस'' में आधुनिक परिपेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है।

5 प्लेटो अपने न्याय सिद्धान्त को किस रुप में प्रतिपादित करता है ?

उत्तर– प्लेटो अपने न्याय सिद्धान्त को एक नैतिक सिद्धान्त के रुप में प्रतिपादित करता है।

6 "जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है" संत ऑगस्टाइन ने किस रचना में लिखा है ?

उत्तर– 'द सिटी ऑफ गॉड' में

7 'परम्परागत न्याय' के दो प्रमुख विचारकों के नाम लिखिए ?

उत्तर– प्लेटो और अरस्तु परम्परागत न्याय के दो प्रमुख विचारक हैं।

शेखावाटी मिशन–100

लघुतरात्मक प्रश्न

1 वितरणात्मक न्याय व सुधारात्मक न्याय में क्या अन्तर है ?

उत्तर– वितरणात्मक न्याय–वितरणात्मक न्याय के अन्तर्गत शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरुप होता है। वह आनुपातिक समानता का पक्षधर है।

सुधारात्मक न्याय–सुधारात्मक न्याय का आशय ऐसे न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, सम्पति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे।

2 कानूनी न्याय के दो आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं ?

उत्तर– (1) सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए तथा

(2) सरकार द्वारा कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए और कानून उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

3 न्याय के परम्परागत व आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना कीजिए।

उत्तर– (1) परम्परागत न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की अवधारणा कानून, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पर आधारित है।

(2) परम्परागत न्याय का सरोकार व्यक्ति के चरित्र से था, वहीं आधुनिक न्याय का सरोकार सामाजिक न्याय से है।

4 प्लेटो के न्याय से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर– प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में न्याय सम्बंधी विचारों को स्पष्ट किया है।प्लेटो के अनुसार न्याय से आशय प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कार्य करने एवं दुसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने से है।

5 आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक व राजनीतिक न्याय अर्थहीन है । कैसे ?

उत्तर – आर्थिक न्याय का सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यक्ति – व्यक्ति के बीच गरीब और अमीर भी खाई को दूर किया जा सके। यदि समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं होगी तो समाज में सदैव वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी तथा आर्थिक असमानता व सामाजिक असमानता में वृद्धि होती रहेगी, ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय अर्थहीन हो जायेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अवसरों की समानता का लाभ नहीं उठा पायेगा ।

6 सामाजिक न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – सामाजिक न्याय – सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो तथा सबको अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो ,राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी व प्रशासनिक निर्णयों का निर्माण करे , जो एक समतामूलक समाज का निर्माण करने में सहायक हो । जॉन रॉल्स व कार्ल मार्क्स ने सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया है।

7 जॉन रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के कौनसे दो मौलिक सिद्धान्तों की प्रतिस्थापना करते है ?

उत्तर– जॉन रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के निम्नलिखित दो मौलिक सिद्धान्तों की प्रतिस्थापना करते है –

(1) व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियाँ स्थापित की जाती है ,जो सबके लिए कल्याणकारी हो।

(2) अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इस सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती है।

8 न्याय के निम्न रूपों की विवेचना कीजिए।

(अ) राजनीतिक न्याय (ब) नैतिक न्याय

उत्तर – (अ) राजनीतिक न्याय–राजनीतिक न्याय से आशय है – एक राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों को समानता का अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए।राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है, ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधन हैं– वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार आदि।

(ब) नैतिक न्याय – न्याय की मूल अवधारणा नैतिकता पर आधारित है । इसमें कुछ सर्व व्यापक अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों को निरूपित करते हैं, इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। सामान्य अर्थ में जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। प्लेटो से लेकर वर्तमान तक के सभी चिंतक सत्य, करूणा, अहिंसा, उदारता आदि सद्गुणों को नैतिक सिद्धान्त मानते है।

शेखावाटी मिशन–100

अध्याय–2
शक्ति सत्ता और वैद्यता

अति लघूतरात्मक प्रश्न –1

प्रश्न–1 'शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है ' किसका कथन है ?

उत्तर– यह कथन आर्गेन्सकी का है।

प्रश्न–2 वैधता प्राप्ति के साधन कौनसे हैं ?

उत्तर– मतदान, जनमत संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि।

प्रश्न–3 शक्ति का प्रयोग करने वाले अनौपचारिक अंग कौन – कौन से हैं ?

उत्तर– दबाव समूह, राजनीतिक दल एवं प्रभावशाली व्यक्ति।

प्रश्न–4 टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।

उत्तर– टॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 'लेवियाथन' है।

प्रश्न–5 शक्ति की कोई दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर– (1) शक्ति दमनात्मक होती है।
(2) शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरूद्ध किया जा सकता है।

प्रश्न–6 घर में वृद्धजनों की सत्ता किस सत्ता का उदाहरण है ?

उत्तर– परम्परागत्त सत्ता।

प्रश्न–7 भारत के किस राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने विरोधियों के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों में संलग्न हैं ?

उत्तर– केरल।

प्रश्न–8 राजनीति विज्ञान को 'शक्ति का विज्ञान' किसने कहा ?

उत्तर– केटलिन ।

प्रश्न–9 शक्ति व सत्ता के बीच की कडी कौनसी है ?

उत्तर– वैधता।

प्रश्न–10 'सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है' किसका कथन है ?

उत्तर– हैनरी फेयोल का।

लघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 शक्ति और बल में सोदाहरण अन्तर बताइए।

उत्तर– शक्ति और बल में अन्तर –1. शक्ति प्रच्छन्न बल है जबकि बल प्रकट शक्ति है। 2. शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। उदाहरण के लिए पुलिस के पास अपराधी को दण्डित करने की शक्ति रहती है लेकिन जब वह वास्तव में उसे दण्ड देती है जो कि आर्थिक व शारीरिक कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है।

प्रश्न–2 सत्ता की स्वीकृति या पालन के लोकप्रिय आधार बताइए।

उत्तर– सत्ता की स्वीकृति या पालन के लोकप्रिय आधार निम्नलिखित है– विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव ।

प्रश्न–3 शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएँ है ?

उत्तर– शक्ति और प्रभाव में निम्नलिखित समानताएँ है–
(1) शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते है । प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को।
(2) शक्ति व प्रभाव को दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते है।

प्रश्न–4 सत्ता पालन के कोई दो आधारों को लिखिए।

उत्तर– (i) विश्वास – सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। यह विश्वास, जितना गहरा होगा सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी।
(ii) एकरूपता–विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञापालन की स्थिति को पैदा करती है।

प्रश्न–5 शक्ति के विविध रूपों का नामोल्लेख कीजिए।

उत्तर– शक्ति के तीन रूप है–
(1) राजनीतिक शक्ति (2) आर्थिक शक्ति (3) विचारधारात्मक शक्ति

प्रश्न–6 मार्क्सवाद की अवधारणा का मूल क्या है ?

उत्तर– मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित होकर किया जाता है। इस आधार पर मार्क्सवाद की मान्यता है कि माँ अपने बच्चे का पालन पोषण अथवा सन्तान अपने माता – पिता की सेवा केवल आर्थिक हितों के लिए ही करते है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न–7 बहुलवादी सिद्धान्त की अवधारणा क्या है ?

उत्तर– बहुलवादी सिद्धान्त के अनुसार समाज की सम्पूर्ण शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बँटी हुई होती है।

प्रश्न–8 परम्परागत सत्ता से क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर– परम्परागत सत्ता– इस सत्ता का आधार परम्पराऐं एवं इतिहास होता है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परम्परा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। इस सत्ता में तर्क एवं बुद्धिसंगतता का अभाव रहता है। घर में वृद्धजनों की सत्ता परमपरागत सत्ता का उदाहरण है।

प्रश्न–9 करिश्माई सत्ता किसे कहते है ? कोई दो भारतीय ' करिश्माई ' नेताओं का नाम बताइये।

उत्तर– करिश्माई सत्ता– यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिक गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है, भारतीय ' करिश्माई ' नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गाँधी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख हैं।

प्रश्न–10 वर्ग प्रभुत्व का सिद्धान्त एवं विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त में अन्तर बताइये।

उत्तर– वर्ग प्रभुत्व का सिद्धान्त– यह मार्क्सवाद की देन है। जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बटा होता है, आर्थिक रूप से ताकतवर बुर्जआ वर्ग(पूँजीपति वर्ग) तथा आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग(मजदूर वर्ग)।

जबकि–

विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त– के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गो विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार वर्ग विभाजन के अनेक आधार जैसे कुशलता, संगठन क्षमता, बुद्धिमता प्रबंध ा व नेतृत्व क्षमता आदि होते हैं।

दीर्घलघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 शक्ति के बहुलवादी सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– शक्ति का बहुलवादी सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त मानता है कि समाज की सम्पूर्ण शक्ति एक वर्ग विशेष के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बँटी होती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में इन समूहों के मध्य सौदेबाजी चलती रहती है। इस प्रकार शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। यहीं अवधारणा शक्ति के भारतीय विचारकों की है। इनकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है–सार्वजनिक हित के लिए शक्ति प्रयोग। इस प्रकार कमजोर वर्ग को शक्ति सम्पन्न बनाकर उन्है समान स्तर पर लाना ही शक्ति है।

प्रश्न–2 शक्ति के विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– शक्ति का विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त शक्ति के आधार पर समाज की दो वर्गों में बाँटता है–

(1) विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली होता है तथा (2) सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है।

समाज का यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं अपितु कुशलता संगठन क्षमता, बुद्धिमता, प्रबन्धन क्षमता, नेतृत्व क्षमता, आदि के आधार पर भी होता है।प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में एक छोटा वर्ग होता है जो शक्तिशाली होता है और सामान्य जनों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।उदाहरण के रूप में देश के राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निमार्ण करते है जो सदैव शक्तिशाली बने रहते हैं। चाहे औपचारिक रूप में किसी भी राजनीतिक दल की देश में सरकार क्यों न हो।

प्रश्न–3 शक्ति के वर्ग – प्रभुत्व सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– वर्ग प्रभुत्व सिद्धान्त मूलतः मार्क्सवाद की देन है। इसके अनुसार आर्थिक आधार पर समाज दो वर्गों में बँटा है–

(1) बुर्जुआ वर्ग जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है तथा

(2) सर्वहारा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है।

इन दोनों वर्गों में निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार '' अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। '' मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ से जुडा होता है, चाहै वह माता – पिता द्वारा बच्चे का पालन–पोषण हो अथवा सन्तान द्वारा माता – पिता की सेवा।

शेखावाटी मिशन–100

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 शक्ति क्या है ? इसके विविध रूप बताइये।

अथवा

शक्ति की अवधारण पर एक लेख लिखिए।

उत्तर– शक्ति का अर्थ –

शक्ति दूसरों के कार्यों व्यवहारों एवं विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। ऑर्गेन्सकी के शब्दों में ''शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है '' राबर्ट वायर्सटेड के अनुसार '' शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग''

लेकिन समकालीन सामाजिक चितन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है–कुछ करने की शक्ति अर्थात् जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है तथा वह इसी अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है।

शक्ति के विविध रूप

मोटे रूप से शक्ति के निम्नलिखित तीन प्रमुख रूप है–

(1) राजनीतिक शक्ति– राजनीजिक शक्ति से तात्पर्य है–समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे– पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, कर, दण्ड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। राजनैतिक शक्ति के प्रयोग करने वाले औपचारिक अंग हैं – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा इसके प्रयोगकर्ता, अनौपचारिक अंग हैं – दबाव समूह, राजनैतिक दल, प्रभावशाली व्यक्ति आदि।

(2) आर्थिक शक्ति– आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन सम्पदा पर स्वामित्व। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते है वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले अनेक तत्वों में आर्थिक शक्ति भी एक तत्व है जबकि मार्क्सवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाला आर्थिक एकमात्र तत्व है।

(3) विचारधारात्मक शक्ति – विचारधारा का अर्थ है – विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। विचारधारा लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है। इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्म मानववाद इत्यादि ऐसी ही विचारधाराएँ है।

प्रश्न–2 सत्ता पालन के आधार एवं उसके विविध रूपों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए।

अथवा

सत्ता क्या है ? इसके विविध रूप बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि हम इसका पालन क्यों करते हैं ?

उत्तर– सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है, जिसके कारण उसे सहीं मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है।

सत्ता पालन के आधार निम्नलिखित है–

(i) विश्वास –सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। यह विश्वास जितना गहरा होगा सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही सरलता से होगी। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है।

(ii) एकरूपता – विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञापालन की स्थिति को पैदा करती है।

(iii) लोकहित – लोक कल्याण भी सत्ता पालन का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दण्ड शक्ति के दबाव में नहीं करते अपितु इसलिए करते है कि लोकहित को बढावा मिले।

(iv) दबाव – अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करना होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव रहता है और वो दमन एवं दबाव की भाषा समझते है।

सत्ता पालन के रूप निम्नलिखित हैं –

(i) परम्परागत सत्ता– इस सत्ता का आधार परम्परा एवं इतिहास होता है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परम्परा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए।

(ii) करिश्माई सत्ता – यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित है, इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बडे से बडा त्याग करने को तैयार रहती है इसमें सत्ता का आधार षवनाएँ होती है, जैसे– महात्मा गाँधी, पं. नेहरू, इन्दिरा गाँधी, अटल विहारी वाजपेयी आदि करिश्माई सत्ता के उदाहरण है।

(iii) कानूनी, तर्कसंगत सत्ता– इसका आधार पद होता है व्यक्तित्व नहीं। उस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता आदि। यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक हो तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे– प्रधानमंत्री में कानूनन समान सत्ता निहित होती है लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग–अलग दिखती है।

अध्याय–4
स्वतन्त्रता एवं समानता

अति लघूरात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 'स्वतंत्रता' का अर्थ क्या है ?

उत्तर– स्वतंत्रता का अर्थ नागरिकों के सर्वागीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं से है।

प्रश्न–2 ''मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किन्तु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है।'' यह कथन किसका है ?

उत्तर– यह कथन रूसो का है

प्रश्न–3 'लोकतंत्र की आत्मा' किस स्वतंत्रता को माना जाता है ?

उत्तर– राजनीति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है।

प्रश्न–4 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है ?

उत्तर– अनुच्छेद – 32

प्रश्न–5 स्वतंत्रता के सम्बन्ध में ' स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा ' यह नारा किसने दिया है ?

उत्तर– बाल गंगाधर तिलक ने।

प्रश्न–6 राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन क्यों हो जायेगी ?

उत्तर– राजनीतिक समानता के बिना नागरिको का बडा समूह शासन में भागीदारी से वंचित हो जाएगा इससे स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी।

प्रश्न–7 किस देश के नागरिकों को समानता, मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है ?

उत्तर– भारत।

प्रश्न–8 पूँजीवादी देशों में किस समानता का अभाव पाया जाता है ?

उत्तर– आर्थिक समानता।

प्रश्न–9 ''प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है'' यह कथन किसका है ?

उत्तर– जे. एस. मिल का।

प्रश्न–10 स्वतंत्रता के बारे में पेट्रिक हैनरी का प्रसिद्ध कथन क्या है ?

उत्तर– ''मुझे स्वतन्त्रता दीजिए या मृत्यु''– पेट्रिक हैनरी।

लघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 'अवसर की समानता' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

उत्तर– 'अवसर की समानता'– अवसर की समानता से आशय है राज्य अपने समस्त नागरिको कों अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है तथा राज्य जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है।

प्रश्न–2 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता' का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– राष्ट्रीय स्वतंत्रता –कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचालक है अर्थात् वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है । राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएँ गौण है।

प्रश्न–3 स्वतंत्रता के मार्ग की दो प्रमुख बाधायें लिखिये ?

उत्तर– स्वतंत्रता के मार्ग की दो प्रमुख बाधायें है–

(1) अशिक्षा (2) गरीबी

प्रश्न–4 नागरिक समानता का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– नागरिक समानता राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य द्वारा अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाये जिससे नागरिको के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके। विधि के शासन द्वारा नागरिक समानता स्थापित की जा सकती है।

प्रश्न–5 'आर्थिक समानता' का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– आर्थिक समानता– आर्थिक समानता से आशय है– सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाये जाएँ तथा सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

शेखावाटी मिशन–100

दीर्घलघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 समानता के आधारभूत तत्वों की विवेचना कीजिये।

उत्तर– समानता के आधारभूत तत्व–

(1) समान लोगों के साथ समान व्यवहार ही समानता है

(2) समस्त लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो।

(3) मानवीय गरिमा एवं अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो।

(4) राज्य समाज के समस्त लोगों के साथ समान आचरण एवं व्यवहार करे।

(5) समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, गुण, वर्ण, भाषा लिंग, निवास स्थान, सम्पति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएं।

(6) प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व प्रदान किया जाएं।

प्रश्न–2 स्वतंत्रता एवं समानता के परस्परिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

उत्तर– स्वतंत्रता एवं समानता एक – दूसरे पर आश्रित व पूरक है–

(1) राजनीनिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी क्योंकि नागरिकों का बडा समूह शासन की भागीदारी से वंचित

(2) नागरिक समानता के अभाव में व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपयोग करने के अवसर नहीं मिलेंगे।

(3) सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जायेगी।

(4) आर्थिक समानता के अभाव में सम्पति का केन्द्रीकरण पूंजीपतियों के हाथों में हो जाने से शेष समाज उनके रहमो–करम पर जियेगा।

अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों आवश्यक है।

प्रश्न–3 स्वतंत्रता के कोई चार प्रकारों की विवेचना कीजिये।

उत्तर– (1) प्राकृतिक स्वतंत्रता –प्राकृतिक स्वतंत्रता से आशय है कि स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ उसके व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तान्तरण नहीं कर सकता है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है और राज्य की स्थापना के साथ यह स्वतंत्रता धीरे – धीरे लुप्त हो जाती है।

(2) व्यक्तिगत स्वतंत्रता– यह स्वतंत्रता व्यक्ति के अपने निजी कार्यो से संबंधित है। व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यो में समाज केवल सामाजिक हित में बंधन लगा सकता है।

अतः वेशभूषा , खान–पान , रहन–सहन , परिवार , धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

(3) राजनीतिक स्वतंत्रता– राज्य के कार्यो व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में भाग लेने एवं सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है।

(4) नागरिक स्वतंत्रता– एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएँ जिन्हे समाज स्वीकृति प्रदान करता है और राज्य मान्यता देकर उनका संरक्षण करता है नागरिक स्वतंत्रताएँ कहलाती है।

प्रश्न–4 स्वतंत्रता की सकारात्मक विचारधारा की विवेचना कीजिये।

उत्तर– स्वतंत्रता की सकारात्मक विचारधारा की मान्यताएँ –

(अ) स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध आवश्यक हैं

(ब) व्यक्ति एवं समाज के हित परस्पर निर्भर हैं

(स) स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है

(द) राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है।

प्रश्न–5 ''विधि का शासन'' अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– विधि का शासन – विधि का शासन अवधारणा का तात्पर्य है कानून या विधि के अनुसार शासन संचालन तथा कानूनी समानता की स्थापना। कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण । कानून के समक्ष समानता का आशय है बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना और कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य है– सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय का एक जैसे अपराध पर समान दण्ड ।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न–6 स्वतंत्रता के लिए आवश्यक चार शर्तो का उल्लेख कीजिए ।

उत्तर– स्वतंत्रता के लिए आवश्यक चार शर्ते –

(i) स्वतंत्रता के प्रति निरन्तर जागरूकता,

(ii) नागरिकों की निडरता एवं साहस,

(iii) समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का उत्पन्न होना

(iv) स्वतंत्र न्यायपालिका ।

प्रश्न–7 स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी हैं– स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर– स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर विरोधी हैं इस विचार को मानने वालो का कहना है कि इन दोनों में कोई साम्यता नहीं है। लार्ड एक्टन की मान्यता है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को ही नष्ट कर दिया है। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में ही असमानता विद्यमान है । योग्य तथा अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नही है और न ही वास्तविक रूप से समानता स्थापित की जा सकती है। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को ही स्थापित किया जा सकता है।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली किन्हीं चार बाधाओं को सोदाहरण बताइये ।

उत्तर– (i) अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव–यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता का हनन कर उसका शोषण कर सकते हैं ।

(ii) अशिक्षा –शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान कराती है । वह स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट करती है । यदि व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे स्वतंत्रता के महत्व का ज्ञान नहीं होगा ।

(iii) गरीबी तथा संसधानों का अभाव–गरीबी तथा संसधानों का अभाव व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधा है उसके लिए स्वतंत्रता की तुलना में रोजी–रोटी के साधन जुटाना अधिक महत्वपूर्ण होता है ।

(iv) न्यायपालिका के कार्यो में कार्यपालिका का हस्तक्षेप – स्वतंत्रता की पहली शर्त स्वतंत्र न्यायपालिका का होना है। यदि शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यो में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी नहीं रह सकती ।

प्रश्न–2 समानता का अर्थ बताते हुए दूसरे विविध प्रकारो की विवेचना कीजिए ।

उत्तर– समानता का अर्थ–समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हैतु समान अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किया जा सके।

समानता के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है –

(i) नागरिक समानता –राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य द्वारा अपने नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके ।

(ii) राजनीतिक समानता –राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यो में भाग लेने की समानता हो। सभी वयस्क नागरिको को समान रूप से मताधिकार निर्वाचन हेतु खडे होने , सार्वजनिक पदों के प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो।

(iii) सामाजिक समानता–सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हो, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो।

(iv) प्राकृतिक समानता–इस अवधारणा के प्रतिपादक मानते है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है उनमें एक जैसा शरीर एवं वृद्धि होती है।

(v) आर्थिक समानता– आर्थिक समानता से आशय है – सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ तथा सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

(vi) सांस्कृतिक समानता–राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है।

(vii) कानूनी समानता – राज्य द्वारा कानूनी समानता का आशय है कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण , अर्थात् सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय एवं एक जैसे गुनाह पर समान दण्ड की व्यवस्था।

शेखावाटी मिशन–100

इकाई – 3
आधुनिक राजनीतिक अवधारणाऐं
अध्याय –1 राजनीतिक समाजीकरण

प्रश्न 1. राजनीतिक समाजीकरण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– राजनीतिक समाजीकरण प्रशिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के लिए स्वीकार्य मानकों और व्यवहारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित किया जाता है।

प्रश्न 2. राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किस विद्वान ने की थी?

उत्तर– हरबर्ट साइमन ने।

प्रश्न 3. "पोलिटिकल सोशलाईजेशन" पुस्तक के लेखक कौन है?

उत्तर– हरबर्ट साइमन।

प्रश्न 4. राजनीतिक समाजीकरण के दो अभिकरणों के नाम लिखों?

उत्तर– (i) परिवार। (ii) शिक्षण संस्थाएँ।

प्रश्न 5. जन संचार के तीन माध्यम बाताईए?

उत्तर– (i) समचारपत्र (ii) टी.वी. (iii) रेडियों

प्रश्न 6. विधार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है ?

उत्तर– शिक्षण संस्थाओं में।

प्रश्न 7. राजनीतिक समाजीकरण का प्रथम अभिकरण कौनसा है?

उत्तर– परिवार।

प्रश्न 8. राजनीतिक समाजीकरण की कोई दो विशेषाताएँ लिखों?

उत्तर– (i) यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है

(ii) यह निरन्तर व गतिशील प्रक्रिया है

प्रश्न 9. राजनीतिक समाजीकरण की दो अनौपचारिक संस्थाओं के नाम बताइये?

उत्तर– (i) परिवार। (ii) पड़ौस।

प्रश्न 10. राजनीतिक समाजीकरण के दो राष्ट्रीय प्रतिकों के नाम लिखों?

उत्तर– (i) राष्ट्रगान व (ii) राष्ट्रध्वज।

प्रश्न 11. राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दल कैसे सहायक है?

उत्तर– राजनीतिक दल अपनी नीति, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सम्पादित करते है

प्रश्न 12. राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन कौन–कौनसे है, लिखों?

उत्तर– (i) परिवार। (ii) शिक्षण संस्थाएँ। (iii) राजनीतिक दल।

(iv) राष्ट्रीय प्रतीक। (v) जनसंचार के साधन।

प्रश्न 13. राजनीतिक समाजीकरण की आमण्ड व पावेल ने क्या परिभाषा दी ?

उत्तर– "राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेणाओं को बनाया जाता है"।

प्रश्न 14. राजनीतिक समाजीकरण के कोई दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लिखो ?

उत्तर– (i) एक मनौवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

(ii) यह उद्देश्यपूर्ण व मूल्य आधारित अवधारणा है।

प्रश्न 15. राजनीतिक समाजीकरण के दो उद्देश्यों को बताइए ?

उत्तर– (i) व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना।

(ii) राजनीतिक ज्ञान को विकसित करना।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 16. राष्ट्रीय प्रतीक सामाजीकरण में किस प्रकार सहायक है?

उत्तर– विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीयध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीयगीत आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शो के प्रति नागरिको में आस्था के भाव पैदा किये जाते हैं।

प्रश्न 17. राजनीतिक समाजीकरण के कोई दो प्रमुख कारण लिखों?

उत्तर– (i) राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी हस्तांतरित करती है

(ii) यह राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहयोग करता है।

प्रश्न 18. राजनीतिक सामाजीकरण व राजनीतिक संस्कृति में सम्बन्ध कैसा है ?

उत्तर– राजनीतिक सामाजीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि राजनीतिक सामाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण, संरक्षण परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होता है

लघुतरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. राजनीतिक दल राजनीतिक सामाजीकरण को कैसे प्रभावित करते है ?

उत्तर – (i) राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को अपने अनुकूल सामाजीकरण करने का प्रयत्न करते है।

(ii) नवोदित राष्ट्रों में राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक संस्कृति के सृजन एवं परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

(iii) ये चुनाव के समय नारे, दीवार लेखन, पोस्टर, रैलियां, चुनाव सभाओं व हित समूहों के द्वारा जनता की अभिवृतियों को अपने अनुकूल बनाते है।

प्रश्न 2. राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं का महत्व बताइये ?

उत्तर – (i) बालक शिक्षण संस्थाओं में जो सीखता है वहीं राजनीतिक समाजीकरण की दिशा निर्धारित करते है।

(ii) शिक्षित लोग अशिक्षित लोगों की तुलना में राजनीति के प्रति अधिक जागरूक एवं सहभागी होते है।

(iii) विचारधाराओं के प्रति निष्ठाओं का निर्धारण भी छात्र जीवन से ही होता है।

(iv) विद्यार्थी जीवन में संगठन क्षमता, नेतृत्व व निर्णय प्रक्रिया को विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओ से ही सीखता है।

प्रश्न 3. परिवार की राजनीतिक समाजीकरण में क्या भूमिका है ?

उत्तर – परिवार पारिवारिक आज्ञापालन के रूप में व्यक्ति को सत्ता का बोध कराते हैं तथा यह सहयोग और दबाव के माध्यम से उसे अनुकरण करना सीखाते हैं। इन्हीं से परिवार द्वारा राजनीतिक समाजीकरण होता है।

प्रश्न 4. राजनीतिक समाजीकरण को जनसंचार के साधन कैसे प्रभावित करते हैं ?

उत्तर – (i) जनसंचार के साधन लोगों की राजनीतिक अभिरूचि एवं विचारधारा के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

(ii) जनसंचार के साधनों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाएँ अपने अनुकूल राजनीतिक अभिमुखीकरण का प्रयत्न करते है जिससे व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलती है।

प्रश्न 5. राजनीतिक समाजीकरण का महत्व बताइये (कोई चार)

उत्तर – (i) राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में सहायक (ii) राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में सहायक

(iii) राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायक (iv) राजनीतिक आदर्शों के निर्धारण में सहायक।

प्रश्न 6. राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधनों का वर्णन करों ।

उत्तर – नोट इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 1 से 4 व 16 को देखें।

शेखावाटी मिशन–100

अध्याय – 2 राजनीतिक संस्कृति

प्रश्न 1. "आधुनिक राजनीति और सरकार" नामक पुस्तक किसने लिखी थी?

उत्तर– एलन बाल ने।

प्रश्न 2. भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अन्तर का प्रमुख कारण क्या है?

उत्तर– राजनीतिक संस्कृति।

प्रश्न 3. राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन–कौनसे हैं ?

उत्तर– (i) इतिहास। (ii) धार्मिक विश्वास। (iii) भौगोलिक परिस्थिति। (iv) सामाजिक–आर्थिक परिवेश। (v) विचारधाराएँ।

प्रश्न 4. राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौनसे हैं ?

उत्तर– (i) अभिजन संस्कृति। (ii) जनसाधारण की संस्कृति।

प्रश्न 5. राजनीतिक संस्कृति के समर्थक दो विद्वानों के नाम लिखो ?

उत्तर– (i) ल्यूशियन पाई। (ii) सिडनी वर्बा।

प्रश्न 6. आमण्ड व पावेल ने राजनीतिक संस्कृति की क्या परिभाषा दी?

उत्तर– राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृतियों और अभिमुखीकरण की शैली है।

प्रश्न 7. निम्न को सुमेलित कीजिए – विद्वान राजनीतिक संस्कृति का सम्बोधन

उत्तर– ये इसी क्रम में सुमेलित है

(i) आमण्ड	(अ) कार्य के प्रति अभिमुखीकरण।
(ii) डेविड ईस्टन	(ब) पर्यावरण।
(iii) स्पिरों	(स) राजनीतिक शैली।

प्रश्न 8. राजनीतिक संस्कृति की कोई दो विशेषताएँ बताइयें?

उत्तर– (i) समन्वयकारी स्वरूप। (ii) नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। (iii) गतिशीलता।

प्रश्न 9. लोकतांत्रिक देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक संस्कृति कौनसी है?

उत्तर– सहभागी राजनीतिक संस्कृति।

प्रश्न 10. "राजनीतिक संस्कृति" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?

उत्तर– आमण्ड ने।

प्रश्न 11. आदिम समाजों में कौनसी राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है?

उत्तर– संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति।

प्रश्न 12. राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं ?

उत्तर– राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों के मूल्यों, दृष्टिकोणों, विश्वासों, भावनाओं, प्रवृतियों, प्रतिभावों, सामान्य लक्ष्यों तथा सामान्य स्वीकृत नियमों के योग को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं।

प्रश्न 13. आमण्ड तथा पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के कितने अभिमुखीकरण बताये ?

उत्तर– (1) ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। (2) भावनात्मक अभिमुखीकरण (3) मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण।

प्रश्न 14. आमण्ड ने राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व कहाँ किया?

उत्तर– अपनी पुस्तक "कम्पेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम" में 1956 में किया।

प्रश्न 15. आमण्ड व सिडनी वर्बा ने अपनी किस पुस्तक में पाँच देशों की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया?

उत्तर– "दि सिविक कल्चर : पॉलिटिकल एट्टीट्यूडस एण्ड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशन्स" पुस्तक में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरीका व मैक्सिकों का अध्ययन किया।

प्रश्न 16. एस. ई. फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के सेना की भूमिका के आधार पर कितने प्रकार बताये है?

उत्तर– (i) परिपक्व (ii) विकसित (iii) न्यून (iii) न्यूनास्तरीय।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 17. राजनीतिक संस्कृति व सामान्य संस्कृति में क्या अन्तर है, लिखों ?

उत्तर– राजनीतिक संस्कृति सीमित अवधारणा है तथा सामान्य संस्कृति व्यापक अवधारणा है।

प्रश्न 18. राजनीतिक संस्कृति को ल्यूशियन पाई ने क्या परिभाषा दी?

उत्तर– "राजनीतिक संस्कृति का सम्बन्ध अभिवृतियों, विश्वासों, एवं भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता व सार्थकता प्रदान करते हैं।"

प्रश्न 19. वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बतायें?

उत्तर– (A) विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति
(i) संकुचित
(ii) पराधीन
(iii) सहभागी

(B) मिश्रित राजनीतिक संस्कृति।
(i) संकुचित पराधीन।
(ii) संकुचित सहभागी।
(iii) सहभागी पराधीन।

प्रश्न 20. राजनीतिक संस्कृति के घटक कौन–कौनसे हैं, लिखों ?

उत्तर– दो घटक (A) अभिमुखीकरण (B) राजनीतिक विषय।

प्रश्न 21. राजनीतिक संस्कृति के घटक राजनीतिक विषय में क्या–क्या शामिल है?

उत्तर– (1) राजनीतिक व्यवस्था (2) राजनीतिक संरचना (3) समस्याएँ और नितियाँ (4) राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति।

प्रश्न 22. अभिजन राजनीतिक को स्पष्ट कीजिए?

उत्तर– अभिजन राजनीतिक संस्कृति अभिजन कहे जाने वाले लोगों की संस्कृति है जिनकी अल्पसंख्यक होते हुए भी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके पास सम्पूर्ण सत्ता होती है।

लघुतरात्मक प्रश्न –

प्रश्न 23. आंग्ल–अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था क्या है ?

उत्तर – इस राजनीतिक संस्कृति में ब्रिटेन व अमेरिका शामिल हैं तथा इसमें सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति होती है।

प्रश्न 24. महाद्वीपीय–यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर – यह राजनीतिक व्यवस्था फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों में मिलती है। इस व्यवस्था में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप–संस्कृतियाँ भी पाई जाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।

प्रश्न 25. गैर–पश्चिम (पूर्व औद्योगिक राजनीतिक) व्यवस्था क्या है ?

उत्तर – एशिया व अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्पविकसित अवस्था में हैं।

प्रश्न 26. आमण्ड ने सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था की कौनसी विशेषताएं बतायी ?

उत्तर – (i) अधिनायकवादी व्यवस्था
(ii) सर्वाधिकारवादी अलौकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था
(iii) विपक्ष व विरोध की संभावना नहीं होती है।
उदाहरण – चीन व उतरी कोरिया जैसे साम्यवादी देश।

प्रश्न 27. आमण्ड ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताये है वर्णन करो।

उत्तर – चार प्रकार हैं जिनका वर्णन प्रश्न संख्या 23, 24, 25, 26 में किया गया है।

प्रश्न 28. आमण्ड व वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को कितने भागों में बाँटा है ?

उत्तर – तीन भागों में **(i) संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति** – ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी और ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है।

(ii) प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति – राजनीतिक मुद्दों की तो जानकारी होती है लेकिन राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती है।

(iii) सहभागी राजनीतिक संस्कृति – राजनीतिक मुद्दों की जानकारी भी होती है और राजनीतिक भूमिका की समझ भी होती है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 29. राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं इसकी मुख्य विशेषताएं बताइये।

उत्तर – राजनीतिक संस्कृति का अर्थ प्रश्न संख्या 12 व 6 को देखे।

विशेषताएं– **(i) समन्वयकारी स्वरूप** – राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते है तथा यह प्राचीन मूल्यों व नवीन जीवन मूल्यों में समन्वय स्थापित करती है।

(ii) नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण – राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप तो कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरुप योगदान देता है।

(iii) अमूर्त स्वरूप – जनता के मनोमष्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं तथा जनता की मानसिक स्थिति को नही माँपा जा सकता है अतः ये राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते है।

(iv) गतिशीलता – व्यक्ति व समाज के जीवन मूल्य, परिस्थितियाँ और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते हैं, इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है।

प्रश्न 30. इतिहास राजनीतिक संस्कृति को कैसे निर्धारित करता है?

उत्तर– किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परम्पराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणाली द्वारा होता है, जैसे भारत की राजनीतिक संस्कृति शान्तिवादी व संवैधानिक तथा अर्द्धविकसित देशों की व्यवस्था हिंसक व विकसित देशों की राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरन्तरता का परिणाम है।

प्रश्न 31. राजनीतिक संस्कृति पर धार्मिक विश्वास का प्रभाव पड़ता है स्पष्ट करें?

उत्तर– वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाएँ किस प्रकार की होंगी इस बात को भी निर्धारित करते है।

प्रश्न 32. विचारधाराओं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है? अपने विचार लिखों?

उत्तर– विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूँजीवाद जैसी विचारधाराएँ अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है।

प्रश्न 33. राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण में क्या संबंध है स्पष्ट करों?

उत्तर– राजनीतिक सामाजिकरण व राजनीतिक संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसे–

(i) राजनीतिक संस्कृति को बनाये रखने का कार्य करती है।

(ii) राजनीतिक संस्कृति को बदलने की कार्य करती है। राजनीतिक सामाजिकरण एक विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति स्थिर रखी और बदली जाती है। इस कार्य के लिए व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में लाया जाता है तथा राजनीतिक संस्कृति के नमूने में परिवर्तन भी राजनीतिक समाजीकरण द्वारा किये जाते है।

प्रश्न 34. भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए आप कौनसी राजनीतिक संस्कृति अपनाने पर बल दोगें और क्यों? समर्थन में दो तर्क दीजिएँ।

उत्तर– भारत जैसे देशाों में हम गैर–पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति अपनाने पर बल देंगे। क्योंकि –

(i) भारत जैसे देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया है परन्तु वहाँ का विकास होना अभी शेष है। पश्चिमी प्रभाव के फलस्वरूप लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नौकरशाही एवं निर्वाचन प्रणाली तो अपना ली गई है, लेकिन लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृति का समुचित विकास नहीं हुआ है।

(ii) ऐसे देश में अपनी मूल संस्कृति एवं सामाजिक व्यवहार परम्परागत रूप से राजनीति पर प्रभाव डालते है। परिणामस्वरूप इन देशों में प्रायः करिश्मा प्रधान नेतृत्व पश्चिमी और परम्परागत संस्कृतियों में समन्वय का प्रयास करता है।

प्रश्न 35. राजनीतिक संस्कृति के कोई चार महत्व लिखो ?

उत्तर– (i) राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ता के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु औपाचारिक सस्थाएँ न रहकर राजनीतिक समाज बन गया है

(ii) इसके माध्यम से राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों का समावेश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया है।

(iii) इसके माध्यम से अध्ययन में विवेकशीलता लाने का प्रयत्न किया है।

(iv) इस उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएँ ग्रहण करते है।

प्रश्न 36. राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करों।

उत्तर– इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 6, 12, 18, 19, 16, 23, 24 व 25 को देखें।

शेखावाटी मिशन–100

अध्याय–3

राजनीतिक सहभागिता

प्रश्न 1. राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया?

उत्तर– व्यवहारवादीयों नें।

प्रश्न 2. राजनीतिक सहभागिता के कोई तीन औजार (साधन) कौनसे हैं ?

उत्तर– (1) मतदान करना (2) चुनाव याचिका प्रस्तुत करना (3) राजनीतिक दल को चन्दा देना।

प्रश्न 3. ' प्रशासन गाँवों/शहरों की ओर ' कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है?

उत्तर– जनसुनवाई का।

प्रश्न 4. "प्रत्याह्वान" का क्या तात्पर्य है?

उत्तर– निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाना।

प्रश्न 5. गैर राजनीतिक सहभागिता के कोई तीन साधन बताइये?

उत्तर– (1) सविनय अवज्ञा (2) नूक्कड़ नाटक (3) शासकीय पुरस्कार लौटाना।

प्रश्न 6. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की शुरूवात कहाँ से हुई थी?

उत्तर– स्विट्जरलैण्ड से।

प्रश्न 7. वर्तमान में कौनसा लोकतंत्र प्रचलित है?

उत्तर– सहभागी लोकतंत्र।

प्रश्न 8. राजनीतिक सहभागिता के कोई दो अभिकरणों के नाम लिखों?

उत्तर– (1) दबाब समूह (2) आरम्भक (प्रस्ताव तैयार करना)।

प्रश्न 9. राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है?

उत्तर– जन सामान्य की नीति निर्माण व राजनीतिक गतिविधियों के प्रति रूचि न होना राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण है।

प्रश्न 10. किस देश में जनमत संग्रह द्वारा मत दिया जाता है?

उत्तर– स्विट्जरलैण्ड में।

प्रश्न 11. राजनीतिक सहभागिता के नये आयाम कौनसे हैं ?

उत्तर– इन्टरनेट, कम्प्यूटर व ई–गवर्नेन्स।

प्रश्न 12. शासन संचालन में जनसाधारण को सहभागिता के अवसर कौन प्रदान करता है?

उत्तर – राजनीतिक दल।

प्रश्न 13. काश व मार्श ने राजनीतिक सहभागिता की क्या परिभाषा दी?

उत्तर – "राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केन्द्र में अवस्थित है।"

प्रश्न 14. "सशक्त सहभागीता लोकतंत्र कमजोर उदार लोकतंत्र की तुलना में बेहतर विकल्प है।" यह कथन किसका है?

उत्तर– बेंजामिन बार्बर।

प्रश्न 15. राजनीतिक सहभागिता से क्या अभिप्राय है?

उत्तर– जनसाधारण की राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष व परोक्ष भागीदारी राजनीतिक सहभागिता कहलाती है।

प्रश्न 16. राजनीतिक उदासीनता का क्या अर्थ है?

उत्तर– जब किसी राजनीतिक व्यवस्था के लोग नीति निर्माण, राजनीतिक गतिविधियों एवं चुनाव अभियानों में भाग नहीं लेते हैं तो उसे राजनीतिक उदासीनता कहते हैं।

प्रश्न 17. राजतन्त्रात्मक व लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक सहभगिता में एक अन्तर लिखों?

उत्तर– राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में सीमित सहभागिता होती है जबकि लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यापक सहभागिता होती है।

प्रश्न 18. राजनीतिक सहभागिता के सक्रिय रूप के दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर– (1) राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना (2) चुनाव प्रचार करना।

प्रश्न 19. राजनीतिक सहभागिता के कितने स्वरूप है?

उत्तर– राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप है – (1) विकासपरक (2) लोकतान्त्रिक।

प्रश्न 20. कौनसी शासन व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता के अवसर कम मिलते हैं ?

उत्तर – अधिनायकवादी व्यवस्था में।

प्रश्न 21. राजनीतिक सहभागिता का दुष्परिणाम क्या है ?

उत्तर– अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता विवादों, विघटन एवं अस्थिरता का कारण बनती है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 22. परम्परागत राजनीतिक सहभागिता के कोई दो रूप लिखो ?

उत्तर– (i) सरकार या जन प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क।
(ii) राजनैतिक प्रचार अभियान।

प्रश्न 23. "राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित प्रत्येक पुस्तक, लोकतंत्र से भी सम्बन्धित होती है।" यह कथन किसका है?

उत्तर– पैरी का।

प्रश्न 24. राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए।

उत्तर – (i) शासन व प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदायों को सौंप दिए जाये।
(ii) सार्वजनिक नीतियाँ निर्धारित करने की प्रक्रिया में किसी प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू किया जावें।

प्रश्न 25. राजनीतिक सहभागिता की सीमित सक्रियता से क्या अभिप्राय है?

उत्तर– जनता राजनीतिक प्रक्रिया में कभी कभी और अनौपचारिक ढ़ग से भाग लेती है तथा जनता सार्वजनिक विषयों में अपने सामाजिक व आर्थिक हितों के अनुरूप भाग लेती है।

लघुतरात्मक प्रश्न –

प्रश्न 1. राजनीतिक सहभागिता नागरिक चेतना को कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर– नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर तथा वैचारिक धरातल आदि राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते है। यहीं कारण है कि जिन देशों में साक्षरता का प्रतिशत जितना अधिक होता है वहां नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता व्यापक होती है।

प्रश्न 2. उच्च मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की सहभागिता में अन्तर बताइयें?

उत्तर– उच्च मध्यम वर्ग अधिक सहभागिता करते है क्योंकि व्यवस्था में उनके हित निहित होते हैं तथा निम्न वर्ग में सहभागिता की अभिवृद्धि आर्थिक सुरक्षा के नाम पर की जाती है।

प्रश्न 3. "गरीबी हटाओं" का नारा किसने दिया?

उत्तर– श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने।

प्रश्न 4. राजनीतिक सहभागिता का क्या महत्व है?

उत्तर– (1) राजनीतिक सहभागिता शक्ति के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार रोकने में सहायक है।
(2) राजनीतिक सहभागिता उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है।
(3) राजनीतिक सहभागिता नागरिकों को सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

प्रश्न 5. आप राजनीतिक सहभागिता बढ़ाना चाहते है, उसके पक्ष में दो तर्क दीजिए?

उत्तर– प्रश्न संख्या 24 का उत्तर देखें।

प्रश्न 6. "वर्तमान में राजनीतिक सहभागिता 'अभिजात्य वर्ग' के हाथों में सिमट कर रह गई है।" इस पर अपने विचार दीजिए।

उत्तर– वर्तमान में राजनीतिक सहभागिता में अधिकांश भूमिका अभिजात्य वर्ग ही निभाता है तथा शासन चलाना और सार्वजनिक नितियाँ बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। सामान्य नागरिकों की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसन्द के राजनीतिक दलों के माध यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक ही सीमित है। शासन सता पक्ष या विपक्ष में केवल चुनिन्दा राजनीतिज्ञ ही होते है, जिनमें जनप्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय तथा अग्रिम पंक्ति व्यावसायिक राजनेता भी आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकि पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण में ब्यूरोक्रेट और टैक्नोक्रेट पर निर्भर रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में राजनितिक भागीदारी केवल अभिजात्य वर्ग ही निभाता है।

प्रश्न 7. "राजनीतिक सहभागिता के लिए स्विट्जरलैण्ड विश्व का अग्रणी देश है।" क्यों? स्पष्ट करों।

उत्तर– (i) स्विट्जरलैण्ड की जनता को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार है।
(ii) यहाँ की जनता जनमत संग्रह के द्वारा जनसहमति से देश के कानूनों में भी परिवर्तन कर सकती है।

प्रश्न 8. राजनीतिक सहभागिता के कोई दो स्वरूपों का वर्णन करों?

उत्तर– (A) सामुदायिक गतिविधि :– इसके अन्तर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए (जैसे स्वच्छता, सुरक्षा) एक–दूसरे के साथ मिल–जुलकर कार्य करते है। इसके अलावा कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मामलें को सुलझानें के लिए अपने राजनीतिक जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करता है या जब कोई नागरिक जलसे–जुलूस, विरोध–प्रदर्शन, हड़ताल, धरने या बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो इस कार्यवाही को राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है।
(B) सरकार व नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया :– यह दो तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युतर देता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते है तथा सरकार भी पहल कर सकती है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 9. नागरिक सहभागिता के पक्ष में कोई तीन तर्क दीजिए?

उत्तर– (i) राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है तथा लोग राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से पूर्व अपने लाभ–हानि का आंकलन करके ही इसमें भाग लेते हैं।

(ii) सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को बढ़ाती है।

(iii) नागरिकों में एकजुटता को बढ़ाती है।

प्रश्न 10. नागरिक सहभागिता के सकारात्मक प्रभाव कौन–कौनसे है?

उत्तर– (i) व्यक्ति के हितों की रक्षा करना तथा उन्है बढ़ाना।

(ii) लोगों में एकजुटता की भावना पैदा करती है।

(iii) शासक व शासितों में निकट संबंध बनाती है।

(iv) इसके माध्यम से सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होती है।

प्रश्न 11. राजनीतिक सहभागिता के नकारात्मक पक्षों पर अपने विचार लिखों?

उत्तर– (i) अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता हानिकारक होती है।

(ii) अत्यधिक सहभागिता से जनता भीड़ में बदल जाती है।

(iii) जो सहभागिता नहीं करते उनके अनुभवों एवं योग्यता तथा प्रतिभा से समाज वंचित रहता है।

प्रश्न 12. राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है तथा इसके नकारात्मक व सकारात्मक पक्षों पर अपने विचार लिखों ?

उत्तर– इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 15 व 10 तथा 11 के उत्तर देखें।

प्रश्न 13. दबाव समूह राजनीतिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करते है?

उत्तर– उदार लोकतन्त्र के अन्तर्गत लोगों के ऐसे समूह जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के उद्देश्य से संगठित होते है, अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाते हैं तथा ऐसी नीतियाँ बनाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हो।

प्रश्न 14. "आरम्भक" क्या है?

उत्तर– प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमण्डल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं।

प्रश्न 15. "प्रत्याह्वान" क्या है?

उत्तर– अर्थः– चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना।

संसदीय लोकतंत्र के अन्तर्गत यह प्रथा है कि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही पद से हटाने के लिए विवश करते है।

प्रश्न 16. "जन सुनवाई" क्या है?

उत्तर– वह प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत जन प्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार व उनकी समस्याएँ जानने का प्रयत्न करते है।

प्रश्न 17. सलाहकार परिषदें राजनीतिक सहभागिता कैसे करती है?

उत्तर– आजकल सरकारे अपने विभागों से जुड़े कार्यो के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती है जिसे सलाहाकार परिषद का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 18. राजनीतिक प्रतिहिंसा क्या है?

उत्तर– विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनानें या सार्वजनिक सम्पति को क्षति पहुँचाने की कार्यवाही की जाती है, राजनीतिक प्रतिहिंसा कहते है।

प्रश्न 19. "परिपृच्छा" क्या है?

उत्तर– अर्थः– किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान।

वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जैसे कि नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जनसाधारण से मतदान कराया जाता है।

प्रश्न 20. सविनय अवज्ञा क्या है?

उत्तर– वह कार्यवाही जिसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर और खुले तौर पर तोड़ा जाता है या निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करके स्वैच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता का और सरकार का ध्यान खींचा जा सके।

प्रश्न 21. राजनितक सहभागिता के प्रमुख अभिकरणों की जानकारी देते हुए उनका इस प्रक्रिया में योगदान बताइयें ?

उत्तर– इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 14 से लेकर 20 तक देखें।

नोट :– राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक सहभागिता में समाजशास्त्रीय संकल्पनाएँ है जिनकों व्यवहारवादी क्रान्ति के अन्तःअनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है।

शेखावाटी मिशन–100

इकाई – 4
भारतीय राजनीति के उभरते आयाम
पाठ–1 नियोजन एवं विकास, नीति आयोग

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. नीति आयोग का गठन कब हुआ ?

उत्तर :– 1 जनवरी, 2015

2. नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हैं ?

उत्तर :– प्रधानमंत्री

3. 'प्लान्ड इकोनोमी फोर इण्डिया' नामक पुस्तक के लेखक थे–

उत्तर :– एम. विश्वेश्वरैया

4. वर्तमान में हमारे देश में नियोजन का कार्य कौनसी संस्था कर रही है ?

उत्तर :– नीति आयोग

5. योजना आयोग की स्थापना कब की गई ?

उत्तर :– योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई।

6. नीति (NITI) आयोग का पूरा नाम बताइए।

उत्तर :– राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India)

7. नीति अयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की वर्तमान संख्या बताइए।

उत्तर :– नीति अयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की वर्तमान संख्या दो है।

8. क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ?

उत्तर :– क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्षों या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करता है।

9. 'सबका साथ, सबका विकास' नारा किसने दिया ?

उत्तर :– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया।

10. नीति आयोग के उपाध्यक्ष व स्थायी सदस्यों के नाम बताइए।

उत्तर :– उपाध्यक्ष – वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार (अर्थशास्त्री) है
स्थायी सदस्य –वर्तमान में दो पूर्णकालिक सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत व डॉ. विनोद पॉल है।

11. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कौन है?

उत्तर :– अमिताभ कांत।

12. नियोजन को अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सर्वप्रथम किस देश ने स्वीकार किया ?

उत्तर :– सोवियत रूस (1928 में)

13. नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर :– प्रधानमंत्री

14. आर्थिक नियोजन को संविधान की किस सूची में रखा गया है ?

उत्तर :– समवर्ती सूची में।

15. सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा किसे दी गई है ?

उत्तर :– नीति आयोग को सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है।

16. नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं ? इनकी नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर :– केन्द्रीय मंत्रीपरिषद् के चार सदस्य होते है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. नियोजन क्या है ?

उत्तर :– सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम ही नियोजन है। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन व प्रयास व्यवस्थित हों तथा अवधि निश्चित हो।
योजना आयोग के अनुसार, " नियोजन संसाधनों के संगठन की ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है "

शेखावाटी मिशन–100

2. अच्छे नियोजन के चार लक्षण बताइये।

उत्तर :– अच्छे नियोजन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं–

(क) उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

(ख) औद्योगीकरण में क्रमबद्ध वृद्धि।

(ग) भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना।

(घ) शासकीय कार्यतंत्र (नौकरशाही) में पारदर्शिता लाना।

3. भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ? समझाइए।

उत्तर :– (क) देश में उपलब्ध साधनों व स्रोतों का सही आकलन करना।

(ख) देश में उपलब्ध साधनों व स्रोतों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना बनाना।

(ग) सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।

4. भारत में नियोजन की क्या आवश्यकता है ? बताइये।

उत्तर :– भारत में नियोजन की आवश्यकता के निम्न कारण रहे हैं–

(क) भारत की कमजोर आर्थिक स्थिति।

(ख) बेरोजगारी की समस्या।

(ग) आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं।

(घ) देश विभाजन से उत्पन्न समस्याएं।

(ड़) औद्योगिकीकरण की आवश्यकता।

(च) अंग्रेजों की नीतियों के कारण पिछड़ापन व धीमा विकास।

(छ) जनसंख्या दबाव।

5. भारत में नियोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।

उत्तर :– **(क) पूर्ण रोजगार** – भारत जैसे विकासशील देशों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है।

(ख) गरीबी मिटाना – देश के विकास में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है जिसे दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है

(ग) असमानताओं को दूर करना – नियोजन के माध्यम से राज्य ऐसे कदम उठाता है जिससे धन तथा आय का समान रूप से वितरण हो।

(घ) उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग – नियोजन के अंतर्गत देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग सुव्यवस्थित व नियंत्रित तरीके से किया जाता है

(ड) संतुलित क्षेत्रीय विकास – प्रत्येक देश में कुछ क्षेत्र अधिक विकसित तो कुछ कम विकसित होते हैं, नियोजन इनमें संतुलन स्थापित करता है।

6. आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर :– सुपरिभाषित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हैतु संसाधनों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित करने तथा उपयोग में लाने का तरीका।

7. भारत में नियोजन और विकास हैतु कौनसे योजनात्मक प्रयास किये गये ?

उत्तर :– भारत में नियोजन और विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 में एम. विश्वेश्वरैया की पुस्तक "प्लान्ड इकोनोमी फॉर इंडिया" द्वारा किया गया, बाद में 1944 में बंबई योजना, एम.एन.रॉय की जन योजना, श्री मन्नारायण की गांधीवादी योजना और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी इसी दिशा में किये गये सार्थक प्रयास थे। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और फिर उसके स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया।

शेखावाटी मिशन–100

निबंधात्मक प्रश्न

1. नियोजन क्या है ? इसकी आवश्यकता व उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालिए।

उत्तर :– लघूत्तरात्मक प्रश्न संख्या 1, 4 व 5 का उत्तर पढ़े।

2. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के गठन एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

उत्तरः– **नीति आयोग का गठन–** नीति आयोग अर्थात् राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को गठित किया गया। जिसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया है

(क) अध्यक्ष – प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है

(ख) गवर्निंग परिषद् के सदस्य – समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल इसके सदस्य होते है।

(ग) क्षेत्रीय परिषदे – एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार व निर्णय हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन, जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेंगी। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है।

(घ) प्रधानमंत्री द्वारा मनोनित सदस्य – जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता व जानकारी रखते हैं।

(ड) पूर्णकालिक पदाधिकारी – उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, दो पूर्णकालिक सदस्य, आंशिक सदस्य, दो बौद्धिक सम्पदा समूह से आवश्यकतानुसार सदस्य, पदेन सदस्य मंत्रीपरिषद के चार सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते है, सचिव स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिवालय।

नीति आयोग के उद्देश्य :–

(1) राष्ट्रीय विकास तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना

(2) ग्राम स्तर पर ढ़ांचागत विकास की पहल

(3) सभी वर्गों का विकास करना

(4) विकास की दीर्घकालिक नीतियां बनाना

(5) सुशासन की स्थापना करना

(6) पारदर्शिता, समयबद्धता, नवाचार तथा जनकल्याण की पूर्ति करना।

स्पष्ट है कि नीति आयोग सरकार के "थिंक टैंक" के रूप में काम करेगा तथा उसे निदेशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।

शेखावाटी मिशन–100

पाठ–2 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-21 किस स्थान पर आयोजित किया गया?
उत्तर– पेरिस (फ्रांस)।
प्रश्न 2. किसी एक धात्विक खनिज का उदाहरण दीजिए।
उत्तर– रॉक फास्फेट।
प्रश्न 3. विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गाँव में व कब हुई?
उत्तर– 21 सितम्बर, 1730 में खेजड़ली गाँव (जोधपुर) में।
प्रश्न 4. विश्नोई समाज की किस महिला ने सबसे पहले वृक्ष रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी?
उत्तर– अमृता देवी ने।
प्रश्न 5. सी.एफ.सी. गैस का पूरा नाम लिखें?
उत्तर– क्लोरो फ्लोरो कार्बन।
प्रश्न 6. आण्विक ऊर्जा में काम आने वाले मुख्य रासायनिक तत्व का नाम लिखिए?
उत्तर– यूरेनियम।
प्रश्न 7. राजस्थान में पनबिजली उत्पन्न करने वाले जल स्रोतों के नाम बताईये।
उत्तर– (1) चम्बल (2) इंदिरा गाँधी नहर (3) माही नदी
प्रश्न 8. यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का पूरा नाम लिखें ।
उत्तर– यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाईमेंट चेन्ज।
प्रश्न 9. समुद्री सतह में वृद्धि का कारण है–
उत्तर– ग्लोबल वार्मिंग।
प्रश्न 10. जलवायु परिवर्तन पर विश्व स्तर पर सबसे पहला सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित किया गया?
उत्तर– 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम (स्वीडन) में।
प्रश्न 11. ओजोन परत का क्या महत्व है?
उत्तर– ओजोन की परत सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित एवं परावर्तित कर पृथ्वी की रक्षा करती है।
प्रश्न 12. ग्रीन हाऊस गैसों के नाम लिखों?
उत्तर– ग्रीन हाऊस गैसें हैं– क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन–डाई–ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि।
प्रश्न 13. विश्व पर्यावरण की कोई चार समस्याएँ बताइये।
उत्तर– (1) वैश्विक तापमान में वृद्धि (2) ओजोन क्षय (3) मरुस्थलीकरण (4) वनोन्मूलन
प्रश्न 14. रिओ सम्मेलन की दो उपलब्धियाँ बताइये।
उत्तर– (1) जलवायु परिवर्तन सन्धि (2) जैव विविधता पर समझौता।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते है?
उत्तर– वैश्विक तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमारी धरती प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है यह किरणें वायुमण्डल से गुजरती हुई धरती से टकराती है फिर परावर्तित (रिलेक्शन) द्वारा पुनः लौट जाती है। लेकिन वायुमण्डल में घुली विभिन्न गैसों के कारण यह परावर्तित किरणें पुनः नहीं लौट पाती, जिससे वायुमण्डल का तापमान बढ़ जाता है यही ग्लोबल वार्मिंग है
प्रश्न 2. ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है कारण बताइये?
उत्तर– (1) मनुष्य जनित गतिविधियों से कार्बन–डाई–ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है
(2) वाहनों, बिजली बनाने के संयंत्रों, उद्योगों से वातावरण में कार्बन डाई–ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है
(3) वनों की कटाई से पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ गया है
(4) जहरीली गैसों से ओजोन परत को नुकसान पहुँचा है
प्रश्न 3. ग्लोबल वार्मिंग से पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर– (1) समुद्री सतह में वृद्धि हो रही है।
(2) मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
(3) पशु–पक्षियों व वनस्पति पर असर।
(4) सी.एफ.सी. गैसों की बढ़ोतरी से ओजोन परत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 4. पर्यावरण जागरूकता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दिवस कौनसे है?

उत्तर– पर्यावरण जागरूकता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दिवस निम्न है–

1. विश्व पर्यावरण दिवस – 5 जून
2. पृथ्वी दिवस – 22 अप्रैल
3. विश्व ओजोन दिवस – 16 सितम्बर
4. वन महोत्सव – 28 जुलाई
5. विश्व जल दिवस – 22 मार्च

प्रश्न 5. भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को किस तरह महत्त्व प्रदान किया गया है?

उत्तर– भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को व्यापक महत्त्व प्रदान किया गया है ऋग्वेद में जल, वायु व पृथ्वी की देव स्वरूप स्तुति की गई है स्थलीय खण्ड को भूमि अर्थात् सर्वव्यापी मातृभूमि या माँ कहते है क्योंकि यह मनुष्य के कल्याण हेतु सभी वस्तुएँ देती है प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों ने वृक्षों तथा वनों के महत्त्व को स्वीकार किया। उन्होंने इन्हें धर्म में सम्मिलित करके मनुष्य द्वारा उसके संरक्षण पर बल दिया।

प्रश्न 6. 'सिर साटे रूख रहै तो भी सस्तो जाण' इस सम्बन्धित घटना का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।

उत्तर– उपर्युक्त वाक्य का अर्थ है कि हमारे सिर के बदले अगर वृक्ष जीवित रहता है तब भी हम इसके लिए तैयार है। 21 सितम्बर,1730 को राजस्थान के खेजड़ली गाँव में विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृतादेवी के नेतृत्व में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति यह कहते हुए दे दी थी कि 'सिर साटे रूख रहै तो भी सस्तो जाण।'

प्रश्न 7. पेरिस समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर– संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2015 को आयोजित किया गया। इसके प्रमुख बिन्दु निम्न है–

(1) पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को भारत सहित 175 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किये।

(2) इस समझौते के बाद सभी देशों को अपने देश की संसद से इस समझौते का अनुमोदन कराना होगा।

(3) विश्व में कम से कम 55 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार 55 देशों के अनुमोदन करने के 30 दिनों के भीतर यह अस्तित्व में आ जायेगा।

(4) समझौते के तहत सदस्य देशों ने 21वीं सदी में दुनिया के तापमान में वृद्धि दो डिग्री से कम स्तर तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है

(5) पेरिस समझौता विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस समझौते को "धरती के लिए महान दिन" कहा।

प्रश्न 8. उपभोक्तावादी संस्कृति किस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर– उपभोक्तावादी संस्कृति ने पर्यावरण को निम्न नुकसान पहुँचाये है–

(1) उत्पादों की पैकिंग सामग्री व डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा मिलने से अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण दुनिया के समक्ष चुनौती बन गया है

(2) उपभोक्तावादी संस्कृति में ऐशोआराम के इतने साधन जुटाने के बावजूद मनुष्य सन्तुष्ट नहीं है इसके कारण वह मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है

(3) अधिक उत्पादन के कारण उत्पादों का जीवन काल (Life Span) कम होता जा रहा है पुराना सामान शीघ्र अनुपयोगी हो जाता है, नया उत्पाद बिक्री के लिए आ जाता है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

(4) प्राकृतिक संसाधनों की कमी की आशंका बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की खपत हम वर्तमान दर से करते रहे तो भूगर्भ में उपलब्ध ताँबा 277 साल में, कोबाल्ट व प्लेटिनम 400 साल में, पैट्रोल 49 साल में, पैट्रोलियम गैस 60 साल में, कोयला कुछ सौ सालों में धरती से गायब हो जायेंगे।

प्रश्न 9. भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु किये गये प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

उत्तर– भारतीय संविधान द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक प्रावधान किये गये है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है–

(1) अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा।

(2) अनुच्छेद 51'क' में मूल कर्त्तव्यों में वन, झील, नदी व अन्य जीवों की रक्षा करने और उनका संवर्द्धन करने की बात कही गयी है

(3) अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों सें बचना चाहिए जो उनके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचाती है।

(4) अनुच्छेद 252 व 253 पर्यावरण को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए अधिकृत करते है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. ग्लोबल वार्मिंग से क्या अभिप्राय है? इसके कारणों की व्याख्या करते हुये पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत वर्णन किजिए।

अथवा

ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसके कारणों की विवेचना कीजिए?

उत्तर– इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 1 से 3 पढ़े।

शेखावाटी मिशन–100

पाठ–3 भारत और वैश्वीकरण

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. भारत और वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– भारत और वैश्वीकरण से तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ समायोजित करना तथा भारतीय बाजार का राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर विस्तार करना।

प्रश्न 2. निजीकरण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– निजीकरण का अभिप्राय है आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को उत्तरोत्तर कम करना तथा प्रेरणा व प्रतिस्पर्द्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 3. वैश्वीकरण से क्या–क्या लाभ हैं ?

उत्तर– वैश्वीकरण के निम्न लाभ है–

(1) व्यापार एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि (2) अधिक तेज गति से विकास।

प्रश्न 4. भारत में आर्थिक सुधार कब और क्यों प्रारम्भ हुआ?

उत्तर– भारत में आर्थिक सुधार 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रारंभ हुए।

प्रश्न 5. वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर– वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ने लगी है और उसकी जगह न्यूनतम अहस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है।

प्रश्न 6. वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ा?

उत्तर– वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा।

प्रश्न 7. वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के बारे में बताइए।

उत्तर– वैश्वीकरण के अन्तर्गत प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए खोल दिया है।

प्रश्न 8. वैश्वीकरण का जीवन प्रत्याशा पर क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर– वैश्वीकरण के कारण जीवन प्रत्याशा दो गुनी हो गयी है।

प्रश्न 9. भारत में वैश्वीकरण का आरम्भ कब हुआ?

उत्तर– 1991 में।

प्रश्न 10. भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब से मानी जाती है?

उत्तर– 1991 से

प्रश्न 11. 1 जनवरी, 1995 को GATT के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई?

उत्तर– विश्व व्यापार संगठन।

प्रश्न 12. भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया?

उत्तर– तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा।

प्रश्न 13. GATT (गैट) का पूरा नाम लिखिए?

उत्तर– 'जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ'।

प्रश्न 14. WTO का पूरा नाम क्या है?

उत्तर– वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (विश्व व्यापार संगठन)।

प्रश्न 15. दुनिया में आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने वाली किन्हीं दो संस्थाओं के नाम बताइए।

उत्तर– (1) अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF)

(2) विश्व व्यापार संगठन (WTO)।

प्रश्न 16. वैश्वीकरण की दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर– (1) भौगालिक दूरियों का सिमट जाना

(2) ग्लोबल संस्कृति की स्थापना।

प्रश्न 17. उदारीकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर– उदारीकरण से अभिप्राय विभिन्न स्तरों पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करने, आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने तथा राजकीय सहायता को क्रमशः कम करके अन्ततः समाप्त करने से है

शेखावाटी मिशन–100

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. भारत पर वैश्वीकरण के प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर– भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने की। इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहे हैं। वे इस प्रकार हैं–

सकारात्मक प्रभाव –

(1) पूँजी बाजार और वित्तीय सुधारों के लिए कदम उठाये गये।

(2) आयात–निर्यात नीति में सुधार किया गया। इसमें प्रतिबन्धों को हटाया गया।

(3) भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।

(4) प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए और सरकारी तन्त्र की जटिलताओं को हल्का किया गया।

(5) प्रत्यक्ष विदेशी विनिमय में वृद्धि हुई।

नकारात्मक प्रभाव –

(1) भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों और कमजोर भारतीय उद्यमों के बीच प्रतियोगिता के कारण भारतीय उद्यम समाप्त हो रहे हैं।

(2) बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लाभ को अपने मूल देश में निर्यात कर रही हैं।

(3) कार्य संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा सुविधाएँ देकर आर्थिक असमानता को बढ़ा रही हैं।

प्रश्न 2. वैश्वीकरण के परिणामों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

उत्तर– वैश्वीकरण ने आज सम्पूर्ण विश्व को एक ही नेटवर्क के दायरे में बाँध दिया है। एक देश की घटनाओं का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ता है। वस्तुएँ, पूँजी, ज्ञान, संचार, हथियार, अपराध, फैशन, विचार और विश्वास तेज गति से एक देश से दूसरे में पहुँच रहे है। वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति के साथ एक वैश्विक व्यवस्था को जन्म दिया है।

प्रश्न 3. आपके अनुसार हमारे सामाजिक मूल्यों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर– सामाजिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के निम्न प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं–

(1) युवाओं ने पश्चिमी प्रभाव में आकर मान–मर्यादा, रीति–रिवाज का परित्याग कर दिया है।

(2) सामाजिकता का स्थान स्वार्थपरकता ने ले लिया है।

(3) व्यक्ति के नैतिक चरित्र में वैश्वीकरण की विभिन्न नकारात्मक प्रवृत्तियों के प्रभाव स्वरूप ह्रास हुआ है।

(4) मूल्यहीनता बहुल संस्कृति वाले देशों के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुई है।

प्रश्न 4. वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष से आप क्या समझते हैं?

उत्तर– वैश्वीकरण का लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर व्यापाक प्रभाव पड़ा है इस प्रक्रिया से विश्व की परम्परागत संस्कृतियों को सबसे अधिक खतरा पहुँचने की आशंका है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को जन्म देता है, जिसका विभिन्न देशों की संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पाश्चात्य सांस्कृतिक मूल्यों को अन्य विकासशील देशों की संस्कृतियों पर लादा जा रहा है। इससे खान–पान, रहन–सहन व जीवन–शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष यह है कि तकनीक के विकास ने राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सांस्कृतिक बाधाओं को हटाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रश्न 5. वैश्वीकरण का क्या अर्थ है?

उत्तर– वैश्वीकरण पूरे विश्व को एक गाँव बनाने की अवधारणा है। वैश्वीकरण वह व्यवस्था है, जिसमें पूँजी राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर मुक्त रूप से विचरण करती है। विश्व अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को वैश्वीकरण कहा जाता है। इस प्रकार वैश्वीकरण का अभिप्राय है : "उन्मुक्त बाजार एवं प्रतिस्पर्द्धा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समायोजन, राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तित करना।"

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 6. वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– (1) राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में परिवर्तन आया है। अब राज्य लोककल्याणकारी राज्य के साथ आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक तत्व बन गया है।

(2) तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ राष्ट्रों का जीवन स्तर बढ़ा है।

(3) सूचनाओं के तीव्र आदान–प्रदान से नागरिकों का जीवन सहज हुआ है।

(4) वैश्वीकरण राष्ट्र–राज्यों को कमजोर बना रहा है।

(5) पूर्व तथा पश्चिम के बीच शक्ति संघर्ष व शक्ति संतुलन की जद्दोजेहद के स्थान पर शांति, रक्षा, विकास, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्यायालय जैसी कानूनी संस्थाओं का सृजन हुआ है।

प्रश्न 7. वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर– (1) वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पश्चिम के देश एशिया एवं अफ्रीका में अपने बाजार तलाश रहे हैं।

(2) प्रत्येक देश ने अपना बाजार विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दिया है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है।

(4) पूर्व तथा पश्चिम के राष्ट्रों में शक्ति संघर्ष के स्थान पर शक्ति संतुलन का विकास हुआ है।

(5) आयात–निर्यात के नियमों में शिथिलता आई है।

(6) वस्तुओं और पूँजी का प्रवाह तीव्र गति से हो रहा है।

प्रश्न 8. "वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है क्योंकि इसके कई आयाम हैं, जैसे– राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक। यथा–

(1) वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम – वैश्वीकरण से विचारों, पूँजी, सेवा तथा आवाजाही का प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है तथा पूँजी निवेश बढ़ता है।

(2) वैश्वीकरण का राजनैतिक आयाम – वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की अवधारणा ने ले लिया है इसके कारण राष्ट्रीय राज्य की स्थिति कमजोर हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा है।

(3) वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम – वैश्वीकरण का आर्थिक तथा राजनैतिक पक्ष के साथ–साथ सांस्कृतिक पक्ष भी है वैश्वीकरण से हमारी पसंद–नापसंद का निर्धारण होता है इसका हमारे विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. वैश्वीकरण क्या है? इसके राजनीतिक व आर्थिक प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

अथवा

वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके राजनीतिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के उत्तर पढ़े।

शेखावाटी मिशन–100

शेखावाटी मिशन—100

पाठ—4 नवीन सामाजिक आंदोलन

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में सुधारवादी आन्दोलन का कोई एक उदाहरण बताइये?

उत्तर— बेटी बचाओ आन्दोलन।

प्रश्न 2. किसी एक श्रमिक संघ का नाम बताइये।

उततर— भारतीय मजदूर संघ।

प्रश्न 3. नर्मदा बचाओं आन्दोलन का सम्बन्ध किससे है?

उत्तर— नर्मदा बचाओ आन्दोलन का सम्बन्ध नर्मदा नदी पर बने छोटे एवं मझोले बाँधों के निर्माण को रोकना है जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके।

प्रश्न 4. शेतकारी संगठन किस राज्य में सक्रिय है?

उत्तर— शेतकारी संगठन महाराष्ट्र राज्य में सक्रिय है

प्रश्न 5. चिपको आन्दोलन की शुरूआत किस राज्य से हुई?

उत्तर— उत्तराखण्ड से।

प्रश्न 6. नर्मदा बचाओं आन्दोलन की प्रमुख नेता है—

उत्तर— मेधा पाटेकर।

प्रश्न 7. नर्मदा बचाओं आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था?

उत्तर— नर्मदा बाँध से विस्थापित लोगों का उचित पुनर्वास न किया जाना।

प्रश्न 8. जन आन्दोलन से क्या अभिप्राय है?

उत्तर— ऐसे आन्दोलन जो लोगों की समस्या या जनहित को लेकर चलाये जाते है उन्हें जन आन्दोलन कहते हैं।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण सहित समझाइये।

उत्तर— समाजिक सुधार आन्दोलन की निम्न श्रेणियाँ हैं—

(1) क्रांतिकारी — क्रांतिकारी आंदोलन प्रचलित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में आमूल परिवर्तन के पक्षधर है। जैसे— नक्सलवादी, वामपंथी आन्दोलन।

(2) सुधारवादी — सुधारवादी आन्दोलन प्रचलित असमानताओं और सामजिक समस्याओं के धीरे—धीरे सुधार के हिमायती होते है अधिकांश गैर—सरकारी संगठन इसी श्रेणी में आते हैं।

(3) उपचारवादी — उपचारवादी आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित होते हैं। उन विशेष समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं।

(4) वैकल्पिक आंदोलन— सम्पूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने की बात करते है। इसमें सामाजिक मूल्यों में बदलाव भी शामिल होता है। जैसे नारीवादी आंदोलन।

प्रश्न 2. भारत में नवीन सामाजिक आन्दोलनों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर— नवीन सामाजिक आन्दोलनों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित समूहों की चर्चा की जाती है—

(1) कृषक अधिकार आन्दोलन — वैश्वीकरण के बाद भारतीय कृषकों विशेष रूप से लघु कृषकों के हितों की रक्षा के लिए आन्दोलन होते रहे हैं। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीय हितों की रक्षा करना है

(2) श्रमिक आन्दोलन — उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के इस युग में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए श्रमिक समूह सक्रिय हो गए है, जैसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा।

(3) महिला सशक्तिकरण आन्दोलन – इस तरह के आन्दोलनों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापाक जागरूकता उत्पन्न की है। वर्तमान में अनेक समूहों और आन्दोलनों ने महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य बताते हुए भारत में सफल आन्दोलन किये है। राष्ट्रीय सेविका समिति का नाम इनमें अग्रणी है।

(4) विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आन्दोलन – विकास एक अनिवार्य एंव सतत चलने वाली प्रक्रिया है परन्तु इसके कुछ दुष्परिणाम भी आये है। नदियों पर बाँधों के कारण विस्थापन, नदी जल विवाद, सड़क एवं अन्य परियोजनाओं से विस्थापन, पर्यावरण क्षरण इत्यादि।

प्रश्न 3. सुधारवादी आन्दोलन की दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर– सुधारवादी आन्दोलन की निम्न विशेषताएँ हैं–

(1) सुधारवादी आन्दोलन सामाजिक व्यवस्था की जड़ता एवं रूढ़िवादिता को समयानुकूल धीर–धीरे परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं।

(2) सुधारवादी आन्दोलन के लिए सामान्यतः सांविधानिक संसदीय परम्पराओं का सहारा लिया जाता है अधिकांश गैर सरकारी संगठन इसी श्रेणी में आते हैं।

प्रश्न 4. विकास परियोजनाओं के विरूद्ध उठ खड़े हुए किसी आन्दोलन के बारे में बताइए।

उत्तर– नर्मदा बचाओं आन्दोलन – नर्मदा पर बाँध के निर्माण से गुजरात के एक बड़े हिस्से सहित तीन पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।

बाँध निर्माण से सम्बन्धित राज्यों के 245 गाँवों के जलमग्न होने की सम्भावना थी जिससे इस परियोजना का विरूद्ध आन्दोलन चला।

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में नव सामाजिक आन्दोलनों की प्रवृति व प्रकारों पर विश्लेषणात्मक लेख लिखिए।

उत्तर – इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक उत्तर पढ़ें।

शेखावाटी मिशन–100

पाठ–5 सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. सामाजिक व आर्थिक न्याय के सम्बन्ध में संविधान के किस भाग में व्यवस्था की गई है?

उत्तर– भाग चार (राज्य के नीति निदेशक तत्व)।

प्रश्न 2. परम्परागत रूप से शोषित व हाशिए पर स्थित लोगों के उत्थान हेतु संविधान में कौनसा विशेष प्रावधान किया गया है–

उत्तर– आरक्षण की व्यवस्था।

प्रश्न 3. भारतीय संविधान का कौनसा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है–

उत्तर– अनुच्छेद 16।

प्रश्न 4. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून किस तिथि से प्रभावी हुआ–

उत्तर– 1 अप्रैल, 2010 से।

प्रश्न 5. 'भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्त्व नहीं है' यह कथन किसका है–

उत्तर– पं. जवाहर लाल नेहरू का।

प्रश्न 6. महिला आरक्षण से सम्बन्धित कौनसा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अवलम्बित है–

उत्तर– 108वाँ।

प्रश्न 7. सामाजिक न्याय के पक्षधर दो समाज सुधारकों के नाम लिखिए।

उत्तर– महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध।

प्रश्न 8. युद्ध या क्रान्ति का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर– सामाजिक न्याय का अभाव।

प्रश्न 9. भारतीय सामाजिक व्यवस्था में चार वर्ण कौनसे थे?

उत्तर– (1) ब्राह्मण (2) क्षत्रीय (3) वैश्य (4) शूद्र।

प्रश्न 10. आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज में कितने वर्ण पाए जाते हैं? नाम बताइये।

उत्तर– दो वर्ग पाए जाते हैं– (1) शोषक एवं (2) शोषित।

प्रश्न 11. भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?

उत्तर– श्रीमती प्रतिभा पाटिल।

प्रश्न 12. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं?

उत्तर– पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित हैं।

प्रश्न 13. भारतीय संविधान के कौनसे अध्याय में आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाएँ की गई हैं?

उत्तर– भाग –3 (मूल अधिकार)।

प्रश्न 14. आरक्षण हेतु जातियों तथा जनजातियों की अधिसूचना कौन जारी करता है?

उत्तर– राष्ट्रपति।

प्रश्न 15. महिलाओं को आरक्षण किस स्तर पर प्राप्त हो चुका है?

उत्तर– पंचायत तथा नगरपालिका (स्थानीय स्वशासन)।

प्रश्न 16. भारत में दलितों के लिए आरक्षण की माँग सर्वप्रथम किसने की थी?

उत्तर– डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने।

प्रश्न 17. आर्थिक न्याय से क्या आशय है ?

उत्तर– आर्थिक समानता की स्थापना करना।

प्रश्न 18. आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं?

उत्तर– प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन सम्पदा का न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है।

प्रश्न 19. अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से अन्य वर्गो से पीछे रह गये है।

प्रश्न 20. "आर्थिक सुधार और आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता।" यह कथन किसका है?

उत्तर– पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट का ।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 21. आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु दो सुझाव दीजिए।

उत्तर– (1) आर्थिक विषमता को दूर किया जाये ।

(2) असीमित सम्पति के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

प्रश्न 22. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है?

उत्तर– अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है।

प्रश्न 23. किस संविधान–संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया?

उत्तर– 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है?

उत्तर– महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की समाज में दोयम दर्जे की भूमिका को समाप्त करना तथा समाज की मुख्यधारा के साथ जोड़ते हुए सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने से है।

प्रश्न 2. विकास के कारण पैदा हुए कोई चार दुष्परिणाम बताइये।

उत्तर– (1) नदियों पर बाँधों के कारण विस्थापन (2) नदी जल विवाद ।

(3) सड़क एवं अन्य परियोजनाओं से विस्थापन (4) पर्यावरण क्षरण।

प्रश्न 3. महिला सशक्तिकरण के लिए कोई दो सुझाव दीजिए।

उत्तर– (1) महिलाओं के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था की जाए ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। इससे इनका दृष्टिकोण व्यापक होगा और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगी।

(2) महिलाएँ भी पुरुषों के समान सूझ–बूझ रखती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

प्रश्न 4. क्या आप पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों पर आरक्षण के पक्ष में है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर– पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था सही है क्योंकि

(1) यह संस्था तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है जब इसके संगठन में स्त्री व पुरूष दोनों को स्थान मिले।

(2) यदि स्त्रियों कों पंचायतों में आरक्षण दिया जाता है तो पंचायतें और अधिक लोकतान्त्रिकएँ संस्था बनेगी।

(3) यदि पंचायतों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित की जाती है, तो इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा भी मिलेगी।

प्रश्न 5. सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए।

उत्तर– सामाजिक न्याय से अभिप्राय है व्यक्तियों में जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाये तथा व्यक्तियों के साथ ऊँच–नीच व छुआछूत का कोई व्यवहार न किया जाये। सभी को समान रूप से आत्म–विकास के अवसर उपलब्ध हों। सामाजिक असमानता की स्थिति में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को 'भेदमूलक न्याय' अपनाना पड़ता है। जिसके अन्तर्गत विकास क्रम में पिछड़ गए समुदायों को पहचान कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है

प्रश्न 6. आर्थिक न्याय की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर– आर्थिक न्याय से तात्पर्य है – धन व सम्पति के आधार पर व्यक्ति–व्यक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन सम्पदा का न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है। जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्याताएँ पूरी होना। कोई इतना गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो जाए कि वह अपने अस्तित्व व गरिमा को ही खो दे।

प्रश्न 7. भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण कि व्यवस्था क्यों की गई है?

उत्तर – भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य समानता स्थापित करने से है। भारतीय समाज में निम्न समझे जाने वाले कुछ वर्गों के लोग सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण उच्च वर्ग के लोगों में प्रतियोगिता नहीं कर सकते और न ही इनके पास संसाधन हैं। ऐसी स्थिति में इन पिछड़ी जाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 8. महिला आरक्षण बिल संसद में पारित नहीं होने के क्या कारण हैं?

उत्तर – संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के निम्न कारण हैं–

(1) पुरुष वर्ग को परिवार, समाज और राजनीतिक संस्थाओं में पुरुष वर्चस्व को कम होते देखना स्वीकार्य नहीं है।

(2) कई राजनीतिक दल एवं नेता सामाजिक न्याय के आधार पर महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। उनकी धारणा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रश्न 9. आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर– आरक्षण का मुख्य उद्देश्य देश के विशाल पिछड़े वर्ग को न केवल सामाजिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाना है, अपितु उसे राजनीतिक सत्ता में उचित भागीदारी भी दिलाना है, जिसके बल पर वह समाज में उचित स्थान प्राप्त सके।

प्रश्न 10. महिला आरक्षण के पक्ष में दो तर्क दीजिए।

उत्तर– (1) महिला आरक्षण में महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा।

(2) शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में संविधान की भावना के अनुसार महिलाएँ आरक्षण की हकदार है।

प्रश्न 11. महिला आरक्षण के दो सम्भावित परिणाम बताइये।

उत्तर– (1) इससे राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन अधिक सभ्य, शालीन तथा मर्यादित बन सकेगा।

(2) समाज तथा राज्य को अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या की क्षमता एवं योग्यता का लाभ मिल सकेगा।

प्रश्न 12. भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु सुझाव दीजिए।

उत्तर– (1) आर्थिक विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

(2) असीमित सम्पति के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(3) प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करवाकर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

(4) धन का उचित वितरण किया जाना चाहिए।

(5) गरीबों के कल्याण की नवीन योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना।

(6) प्रभावशाली कर प्रणाली की स्थापना व कर प्रणाली में सुधार।

(7) राजनीतिक आधार पर आरक्षण न देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करना।

प्रश्न 13. भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

उत्तर– भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं–

(1) भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है।

(2) संविधान निर्माताओं का मानना था कि मात्र समानता के अधिकार से सदियों से अत्याचार सह रहे वर्गों की स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है इसलिए उनकी स्थिति सुधारने व उनके हितों की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी नौकरियों में तथा विधायिका में आरक्षण भी प्रदान किया गया है

(3) संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय के आदर्श का उल्लेख किया गया है।

प्रश्न 14. महिला आरक्षण का विरोध किन आधारों पर किया जाता है?

उत्तर– महिला आरक्षण का विरोध निम्न आधारों पर किया जाता है–

(1) सत्ता में भागीदारी के आधार पर – यदि एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिये गये तो उसी अनुपात में पुरुषों के लिये सत्ता में भागीदारी के अवसर कम हो जायेंगे।

(2) सामाजिक न्याय के आधार पर – कुछ महिलायें अन्य महिलाओं के मुकाबले अधिक पिछड़ी हुई है। अतः उनके लिए और अधिक विशिष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये। इस रूप में 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' की बात उठायी जाती है

(3) क्षमता व योग्यता के आधार पर – महिला आरक्षण विरोधियों का कहना है कि महिलायें अपनी क्षमता तथा योग्यता के आधार पर आगे बढ़ें। उन्हें या तो समानता का दावा नहीं करना चाहिये या आरक्षण की माँग छोड़ देनी चाहिये।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 15. महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर– महिला आरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं –

(1) उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक– आज भी भारतीय संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, जबकि महिलाओं की आर्थिक तथा सामजिक स्थिति में सुधार लाकर ही उनकी योग्यताओं तथा क्षमताओं का प्रयोग राष्ट्रहित में किया जा सकता है।

(2) महिला–विकास के लिए आवश्यक– महिलाओं के आगे बढ़ने में समाज जनित अनेक बाधाएँ तथा समस्याएँ हैं, जिन्हें लम्बे समय से चली आ रही कुरीतियों तथा कुप्रथाओं के कारण बल मिला है। इन सबका सामना करने के लिये महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता है।

(3) राजनीति तथा जनमत का समर्थन – शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के रूप में संविधान के प्रावधानों तथा भावना के अनुसार महिला आरक्षण की हकदार है और इसके माध्यम से वे अपनी योग्यता के अनुसार राजनीति में प्रवेश कर सकती हैं।

(4) राजनीति में स्वस्थ वातावरण का निर्माण – वर्तमान में राजनीति में हिंसा, अपराध तथा अमर्यादित व्यवहार बढ़ता जा रहा है ऐसी स्थिति में महिलाओं की उपस्थिति ही सार्वजनिक व्यवहार को अधिक मर्यादित तथा सभ्य बनाने में सफल होगी। इसके लिए महिला–आरक्षण दिया जाना आवश्यक है

निबंधात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. कल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय संविधान के उन प्रावधानों की मीमांसा कीजिए जो आर्थिक न्याय की स्थापना के पक्षधर हैं।

उत्तर– भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के प्रावधान– जनकल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं जिनमें प्रमुख निम्न है–

(1) अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों के सम्बन्ध में समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(2) अनुच्छेद 19 (1) 6 में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को कोई भी वृति, व्यापार या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(3) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत भी आर्थिक न्याय के लिए पर्याप्त प्रावधान है। अनुच्छेद 39 में निम्न प्रावधान किये गये हैं–

(i) समान रूप से महिला व पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो।

(ii) समुदाय की भौतिक सम्पति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

(iii) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो कि धन और उत्पादन–साधनों व संसाधनों का केन्द्रीकरण न हो।

(iv) पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता हो।

(v) श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाने के लिए विवश न होना पड़े जो उसकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो।

(vi) समान न्याय एवं विधिक सहायता का प्रावधान है ताकि जो गरीब है या किसी कारण से मुकदमें के दौरान अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकते उनके लिए सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध करवाये।

(4) आर्थिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत में जमींदारी प्रथा व देशी राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त किया गया।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 2. भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु क्या–क्या प्रावधान किये गये हैं ?

उत्तर :– **सामाजिक न्याय का अर्थ** – सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हों।

सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उनके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए।

सामाजिक न्याय हैतु संवैधानिक प्रावधान – भारतीय संविधान के भाग–3 (मौलिक अधिकार) और भाग–4 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) में सामाजिक न्याय को प्राप्त करने वाले विविध उपायों का उल्लेख किया गया है–

(अ) समानता का अधिकार – भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है यथा–

(1) **अनुच्छेद–14** में भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता और अधिनियमों के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की गई है

(2) **अनुच्छेद–15** में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है।

(3) **अनुच्छेद–16** के अंतर्गत राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है।

(4) **अनुच्छेद–17** द्वारा अस्पृष्यता का कानूनी तौर पर अंत कर दिया गया है।

(ब) शोषण के विरूद्ध अधिकार – भारतीय संविधान में शोषण किये जाने के विरूद्ध नागरिकों को अनुच्छेद 23 और 24 में मूल अधिकार प्रदान किये गये है यथा–

(1) **अनुच्छेद–23(1)** के अंतर्गत मानव के क्रय–विक्रय और बलात् श्रम अथवा बेगार पर रोक लगा दी गई है।

(2) **अनुच्छेद–24** कारखानों आदि में बच्चों से काम करवाने (बालश्रम) पर रोक लगाता है।

(स) शिक्षा व संस्कृति संबंधी मूल अधिकार– संविधान अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी सामाजिक न्याय के सोपान है।

(द) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान– संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि मात्र समानता के अधिकार से सदियों से शोषण सह रहे वर्गों की स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी स्थिति सुधारने व उनके हितों की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी नौकरियों तथा विधायिका में आरक्षण भी प्रदान किया गया है।

(य) अन्य प्रावधान– भारतीय संविधान में सामाजिक समानता की स्थापना की दिशा में किए गए अन्य प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है–

(1) **अनुच्छेद–41 व 42** में राज्य को यह उतरदायित्व सौंपा गया है कि वह काम की यथोचित मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करें।

(2) **अनुच्छेद–43** में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध करता है।

(3) **अनुच्छेद–44** नागरिकों के लिए समान नागरिक–संहिता पर बल देता है।

(4) **अनुच्छेद–45** में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की उन्नति पर बल दिया गया है।

(5) **अनुच्छेद–21क** के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। 1 अप्रैल, 2010 को यह लागू हुआ।

शेखावाटी मिशन–100

खंड – ब

इकाई –1

भारत का संविधान

भारतीय संविधान की विशेषताऐं

1. भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा ?

उत्तर – 2वर्ष 11 माह 18 दिन

2. भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया ?

उत्तर – 26 नवम्बर 1949 को

3. भारत का संविधान कब लागू हुआ ?

उत्तर – 26 जनवरी 1950 को

4. किस देश के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया जाता है ?

उत्तर – भारत

5. भारत के संविधान में अंतिम शक्ति किसमें निहित की गयी ?

उत्तर – भारत की जनता में

6. भारत के संविधान में कितने भाग है ?

उत्तर – 22

7. भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है ?

उत्तर – 12

8. "हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है"। कथन किसका है?

उत्तर – हरिविष्णु कामथ

9. अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है?

उत्तर – 7

10. कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद है?

उत्तर – 147

11. दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कितने अनुच्छेद है?

उत्तर – 153

12. ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है?

उत्तर – 128

13. प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किस विद्वान ने कहा ?

उत्तर – श्री के. एम. मुंशी

14. संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके है ?

उत्तर – 104 (जीएसटी –101 वां , एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा –102वां , ईडब्ल्यूएस को आरक्षण –103 वां , एससी एसटी आरक्षण की समय सीमा वृद्धि व आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की समाप्ती – 104 वां)

15. संविधान में भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्रदान किये गये है ?

उत्तर – 6 (संविधान लागू होने के समय 7 थे)

16. 101 वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है ?

उत्तर – जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर)

17. वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ?

उत्तर – 11

18. 44 वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया?

उत्तर – संपति का अधिकार

19. संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है ?

उत्तर – भाग –3 (अनुच्छेद 12 – 35)

20. नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिये गये है ?

उत्तर – आयरलैंड

शेखावाटी मिशन–100

21. मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिये गये है ?
उत्तर – संयुक्त राज्य अमेरिका
22. मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिये गये है ?
उत्तर – सोवियत रूस
23. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संविधन संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
उत्तर – 86 वां संविधान संशोधन 2002 जो कि 1 अप्रेल 2010 से लागू हुआ था।
24. नि‘ःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया ?
उत्तर – 21 क में
25. 86 वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है ?
उत्तर – 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से
26. मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोडे गये ?
उत्तर – 42 वें संविधान संशोधन द्वारा
27. संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है ?
उत्तर – भाग – 4
28. व्यस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गयी थी ?
उत्तर – 61 वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में
29. संविधान में भारतीय संघ के लिये किस शब्द का प्रयोग किया गया है ?
उत्तर – राज्यों का संघ (UNION OF STATES)
30. भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गये ?
उत्तर – 42 वां संविधान संशोधन, 1976 द्वारा
31. संविधान में संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद मे है ?
उत्तर – अनुच्छेद 368
32. किस देश ने अपना संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान को प्रतिमान के रुप में लिया ?
उत्तर – दक्षिण अफ्रीका ने
33. भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है ?
उत्तर – केंद्र सरकार के पास
34. संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है ?
उत्तर – दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
35. संविधान के किस अनुच्छेद में देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल का वर्णन है ?
उत्तर – अनुच्छेद 360 में
36. संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है ?
उत्तर – भाग – 18 में
37. अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है ?
उत्तर – बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में पूरे देश में या किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा ने से संबंधित है।
38. अनुच्छेद 356 में किस विषय का वर्णन है ?
उत्तर – यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाये तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है।
39. संविधान में ”एकल नागरिकता” का प्रावधान किसका परिचायक है ?
उत्तर – देश की एकता का
40. ”वसुधैव कुटुम्बकम” को संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है ?
उत्तर – अनुच्छेद 51 में
41. अनुसूचित जातियों व जन जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ?
उत्तर – अनुच्छेद 330 लोकसभा में एवं अनुच्छेद 332 में राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
42. न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है ?
उत्तर – अनुच्छेद 13 एवं 32 से

43. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्रीय सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई?

उत्तर – 27 प्रतिशत

44. भारत के संविधान में प्रयुक्त "हम भारत के लोग" का क्या अर्थ है ?

उत्तर – भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित एवं स्वीकृत है

45. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ?

उत्तर – राष्ट्रपति द्वारा

46. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर – राष्ट्रपति

47. कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है ?

उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय (न्यायपालिका)

लघूतरात्मक प्रश्न –

1. गणराज्य से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर – भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वशांनुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है शासन सत्ता का अंतिम स्त्रोत जनता में निहित है ।

2. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र का क्या आशय है ?

उत्तर – भारत किसी अन्य देश या बाह्य नियंत्रण से मुक्त है एवं अपने आंतरिक मामलों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नही करता है । साथ ही भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें शासन संचालन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है ।

3. संसदीय शासन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – संसदीय शासन व्यवस्था भारत के संविधान में अपनायी गई है । इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है – एक नाममात्र की कार्यपालिका व दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका (राष्ट्रपति) का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है पर वास्तविक कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) ही शक्तियों का प्रयोग करती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी होती है ।

4. भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, समझाइये।

उत्तर – भारत के संविधान में कठोरता का लक्षण अमेरिकी संविधान व लचीलेपन का लक्षण ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में संशोधन की तीन विधियां है –

(1) संविधान के कुछ भागों में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

(2) कुछ विषयों में बदलाव के लिए संसद के दोनो सदनों के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत व कुल सदस्य संख्या के बहुमत की आवश्यकता होती है।

(3) कुछ विषयों में बदलाव के लिए संसद के दोनो सदनों के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन दोनों का मिश्रण है

5. पंथनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है ?

उत्तर – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है । धर्म के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नही करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नही है

6. समाजवादी राज्य क्या होता है?

उत्तर – भारतीय संविधान में भारत को एक समाजवादी राज्य कहा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि आर्थिक आधार पर व्यक्तियों में बहुत अधिक असमानता न हो ।राज्य अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करेगा।

7. व्यस्क मताधिकार का क्या अर्थ है ?

उत्तर – भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वोट देने का अधिकार मिल जाता है इसे व्यस्क मताधिकार कहते है। मूल संविधान में यह आयु 21 वर्ष थी जिसे 61 वें संविधान संशोधन 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया ।

8. भारतीय संविधान में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श प्रयास किया गया है। लोककल्याणकारी राज्य क्या होता है ?

उत्तर – केंद्र व राज्य सरकारें व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे – पौष्टिक भोजन , आवास , वस्त्र , शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाऐं उपलब्ध करवायें । नागरिको के जीवन स्तर को ऊँचा उठाये। जहाँ तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाये।

शेखावाटी मिशन–100

9. भारतीय संविधान अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था करता है । स्पष्ट कीजिए

उत्तर – भारतीय संविधान के भाग सख्या 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिको को मौलिक अधिकार प्रदान किये गयें है। इसमें वर्तमान में 6 मूल अधिकार – 1. समता का अधिकार, 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किये गये हैं ।

भारतीय संविधान के भाग सख्या 4क में अनुच्छेद 51क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 42 वें सविधान संशोंधन, 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था । 86 वें सविधान संशोंधन 2002 के माध्यम से 1 मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया । वर्तमान में सविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार हम कह सकतें है कि भारतीय संविधान अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था करता है ।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर – उपर्युक्त 1 से 9 तक के प्रश्नों के अनुसार।

पाठ –3

भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व

1. भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है

उत्तर – 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश।

2. संघवाद किसे कहते है ?

उत्तर – सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली प्रणाली संघवाद कहलाती है

3. एकल नागरिकता से क्या आशय है ?

उत्तर – केंद्र व राज्य में से केवल एक की नागरिकता होती है।

4. संघात्मक शासन वाले किन्ही तीन देशों के नाम लिखिए

उत्तर – संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया।

5. भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है ?

उत्तर – कनाडा से।

6. संसद का कौनसा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ?

उत्तर – राज्यसभा।

7. केंद्र व राज्यों में विवादों का निपटारा कौनसी संस्था करती है ?

उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय।

8. सरकारिया आयोग का संबंध किससे है ?

उत्तर – केंद्र व राज्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन करने हेतु इसका गठन किया गया।

9. भारत में केंद्र व राज्यों को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है ?

उत्तर – संविधान से (भारत में संविधान की सर्वोच्चता है)

10. किस देश को "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है ?

उत्तर – भारत को।

11. भारतीय संसद का उच्च सदन कौनसा है ?

उत्तर – राज्यसभा।

12. संविधान की किस अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है ?

उत्तर – 7 वी अनुसूची में।

13. केंद्र सूची में कितने विषय है ?

उत्तर – 97

14. केंद्र सूची पर कानून कौन बनाता है ?

उत्तर – केंद्र/संघ सरकार।

15. राज्य सूची में कितने विषय है ?

उत्तर – 61

16. राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है ?

उत्तर – राज्य सरकार।

17. समवर्ती सूची में कितने विषय है ?

उत्तर – 47

शेखावाटी मिशन–100

18. समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है ?

उत्तर – समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं लेकिन दोनों के कानूनों में विरोधाभास होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा।

19. अवशिष्ट विषयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ?

उत्तर – अनुच्छेद 248

20. राज्य सभा में राज्यो को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है ?

उत्तर – जनसंख्या के अनुपात में

21. किस देश में दोहरी नागरिकता प्रणाली अपनायी गई है ?

उत्तर – अमेरिका और स्वीटजरलैंड में ।

22. संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है ?

उत्तर – अनुच्छेद 312 में

23. भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों से संबंधित प्रावधान किस देश से लिये गये है ?

उत्तर – कनाडा से

24. भारत में संघात्मक व्यवस्था को के. सी. व्हीयर ने क्या कहा ?

उत्तर – अर्द्ध संघीय

25. ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को क्या कहा ?

उत्तर – सहयोगी संघवाद

26. मोरिस जोन्स ने भारतीय संघात्मक व्यवस्था को क्या कहा ?

उत्तर – सौदेबाजी पर आधारित संघवाद

27. अंतर – राज्य परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है ?

उत्तर – अनुच्छेद 263 में

लघुतरात्मक प्रश्न –

1. विधि के शासन से आप क्या समझते है ?

उत्तर – विधि के शासन का अर्थ है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है । केंद्र सरकार , राज्य सरकार व आम नागरिक सभी कानून की दृष्टि से समान है। कानून किसी के साथ भेदभाव नही करता है।

2. संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है?

उत्तर – भारतीय संघवाद में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है , इसका अर्थ है कि भारत में केंद्र व राज्य दोनों को अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है तथा इकाईयों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त नही है।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर – भारतीय संघीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताऐं है –

(1) शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन – संविधान की 7 वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सूची पद्धति के माध्यम से किया गया है । संघ सूची के 97 विषयों पर केंद्र को विधि निर्माण का अधिकार है, राज्य सूची के 61 विषयों पर राज्यों को विधि निर्माण का अधिकार है, जबकि समवर्ती सूची के 47 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है लेकिन दोनों के कानूनों में विरोधाभास होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा।

(2) निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका – संघीय व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का संविधान के प्रावधानों के अनुरूप समाधान करने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है । ऐसे अनेक अवसर आये जब केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढाँचे की रक्षा की गई।

(3) संविधान की सर्वोच्चता – इसकी व्याख्या पूर्व के प्रश्न 1 में कर दी गई है

(4) भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता प्रावधान है । ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावना को रोकने के लिए किया गया है ।

(5) केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा – भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए संसद में उच्च सदन राज्य सभा को राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।

शेखावाटी मिशन–100

(6) राज्यपाल का पद – भारतीय संघवाद में केंद्र व राज्यों में समन्वय बनाने के लिए राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण पद है राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्य में केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है यद्यपि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का पद विवाद का प्रमुख विषय बन गया है किंतु केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में उसकी अपनी उपयोगिता है

(7) एकात्मकता का प्रभुत्व – भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जा सकती है भारत की एकता व अखंडता को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना स्वभाविक था । अर्थात संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को निर्णायक भूमिका प्राप्त है । संविधान संशोधन , राज्यों के निर्माण एवं सीमांकन , आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का पद आदि से केंद्र की स्थिति मजबूत व निर्णायक रखी गयी है

2. भारतीय संघवाद में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण बताइए।

उत्तर – भारतीय संघात्मक व्यवस्था संघात्मक होते हुए भी पूर्ण संघीय नही है क्योंकि इसमें अनेक प्रावधान एकात्मक के है। भारतीय संघवाद में निम्नलिखित एकात्मक लक्षण प्रमुख है –

(1) एकल संविधान – भारत में अमेरिकी संघ की तरह राज्यों व केंद्र का अलग–अलग संविधान नही है। यहाँ संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही संविधान है किसी भी राज्य का अपना संविधान नही है

(2) एकल नागरिकता – भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक है तथा अपने राज्य की कोई नागरिकता नही है

(3) एकीकृत न्यायपालिका – भारत का प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है । राज्यों के उच्च न्यायालयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है इसी प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय उच्च न्यायालयं के अधीन कार्य करते है।

(4) विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ – राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है । राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है।

(5) संविधान संशोधन – संविधान संशोधन हेतु केंद्र को राज्यो से अधिक अधिकार प्राप्त है । अधिकांश कानूनों में संसद राज्यों की सहमति के बिना संशोधन कर सकती है । संविधान के बहुत कम भाग में संशोधन हैतु आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है।

(6) आपातकालीन उपबंध – संविधान के अनुच्छेद 352 , 356 व 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है आपातकाल में राज्यों के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है तथा शासन कार्य केंद्र सरकार के निर्देशन में संचालित किया जाता है।

(7) राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व – राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नही बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है जो संघात्मक प्रंणाली से भिन्न है।

(8) शक्तियों का विभाजन – संविधान में केंद्र सूची में अधिक विषय दिये गयें है जबकि राज्यसूची में में कम विषय है तथा समवर्ती सूची के विषयों पर भी केंद्र के कानून को प्रमुखता दी गई है।

(9) अवशिष्ट विषय – भारत के संविधान में अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है।

इकाई—2
भारत में शासन
संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा

अतिलघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न—1 ऐसे दो क्षेत्र बताइए जिनमें राज्यसभा , लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली है।

उत्तर— (1) कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के क्षेत्र में।
(2) वित विधेयक के क्षेत्र में।

प्रश्न—2 वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य हैं ?

उत्तर— उत्तरप्रदेश जिसमें 80 लोकसभा सदस्य हैं।

प्रश्न—3 गणपूर्ति (कोरम) से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर— सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या (सदन की संख्या का 1/10) जिनकी उपस्थिति से सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती हैं।

प्रश्न—4 भारतीय संसद का महत्वपूर्ण कार्य क्या है ?

उत्तर— भारतीय संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण है।

प्रश्न—5 वर्तमान में लोकसभा में राज्यों से एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं ?

उत्तर— वर्तमान में लोकसभा में राज्यों से 530 एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं

प्रश्न—6 वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन— जाति के लिये कितने स्थान आरक्षित है ?

उत्तर— लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिये 84 एवं अनुसूचित जन— जाति के लिये 47 स्थान आरक्षित है।

प्रश्न—7 किस स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष बढाया जाता है ?

उत्तर— राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक वर्ष बढाया जा सकता है।

प्रश्न—8 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है ?

उत्तर— लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है।

प्रश्न—9 किस विधेयक को पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है ?

उत्तर— धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है।

प्रश्न—10 वर्तमान में कौनसे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहैगी ?

उत्तर— वर्तमान में 84 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहैगी ।

प्रश्न—11 संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है ?

उत्तर— राष्ट्रपति।

प्रश्न—12 किस प्रकार के विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त होती है ?

उत्तर— संविधान संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में।

प्रश्न—13 राज्यसभा वित विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है ?

उत्तर— 14 दिन तक।

लघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न—1 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन— कौनसी योग्यताएँ होनी आवश्यक है ?

उत्तर— (1) वह भारत का नागरिक हो।
(2) उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।
(3) वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
(4) वह ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा समय समय पर निश्चित की जाएँ।
(5) वह किसी न्यायलय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो ।

प्रश्न—2 ऐसी कोई दो निर्योग्यताएँ बताइये , जिनके आधार पर संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है ?

उत्तर— (1) संविधान की 10 वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल — बदल का दोषी पाये जाने पर उसे सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है।
(2) किसी संसद सदस्य को चुनावी अपराध अथवा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है।

प्रश्न—3 सरकारी विधेयक तथा गैर सरकारी विधेयक से आप क्या समझते है ?

उत्तर— यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा गया है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं और यदि विधेयक साधारण संसद सदस्य/सदस्यों द्वारा यदि रखा जाता है तो उसे गैर—सरकारी विधेयक कहते है।

शेखावाटी मिशन—100

प्रश्न–4 हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए जो संशोधन किये गये हैं, वे कौन से हैं ?

उत्तर– (1) प्रत्याशियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया , जिस राज्य से वह निर्वाचित होना चाहता है।

(2) गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था को अंगीकार किया गया।

प्रश्न–5 संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को किन दो प्रकार से बर्खास्त किया जा सकता है ?

उत्तर– 10वीं अनुसूची के अनुसार निम्न प्रावधान हैं–

(1) किसी संसद सदस्य को दल – बदल का दोषी पाये जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है।

(2) सदस्य के चुनावी अपराध अथवा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है।

प्रश्न–6 ''परिसीमन आयोग'' के गठन प्रावधान से आप क्या समझते है ?

उत्तर– संविधान के अनु. 82 में परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आंवटन एवं प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों कर पुनः निर्धारण किया जाएगा।

प्रश्न–7 भारत में संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में कौनसी योग्यताएँ होनी चाहिए?

उत्तर– (1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) राज्यसभा के लिए 30 वर्ष व लोकसभा का सदस्य बनने के लिये उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए।

(3) वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो ।

(4) वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो।

(5) वह संसद द्वारा कानून के अंर्तगत निर्धारित अन्य योग्यताएँ पूरी करता हो।

प्रश्न–8 संसद के दो कार्य लिखिए।

उत्तर– **(1) विधि निर्माण करना–** संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य– संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य करती है, यथा प्रश्न, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा। लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण की सबसे बडी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है।

दीर्घलघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 संसद के सत्र (अधिवेशन) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर– संसद के सत्र– भारतीय संविधान के अनु 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय–समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, लेकिन संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा।

भारत की संसद के प्रतिवर्ष तीन सत्र (अधिवेशन) होते हैं– (1) बजट सत्र (फरवरी–मई), (2) मानसून सत्र (जुलाई–सितम्बर), (3) शीतकालीन सत्र (नवम्बर–दिसम्बर) संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है।

प्रश्न–2 धन विधेयक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर– धन विधेयक–धन विधेयक पारित करना संसद का कार्य है। अनु. 109 में विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है तथा अनु. 110 में इसे परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा के लिये विधेयक को उसे प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। धन विधेयक अनिवार्य रूप एक सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी नहीं।

प्रश्न–3 भारतीय संसद मंत्रिपरिषद पर किन तरीकों से नियंत्रण रखती है, वर्णन कीजिये ।

उत्तर– भारतीय संसद मंत्रिपरिषद पर विभिन्न तरीकों से नियंत्रण रखती है–

(1) भारतीय संसद के दोनों सदन में प्रश्न पूछ कर, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को प्रश्नों व प्रस्तावों के द्वारा कटघरे में खड़ा करते है।

(2) कार्यपालिका पर नियंत्रण की सबसे बडी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, वह है–विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत के पारित न होने और अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का परिणाम मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटना होता है।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न–1 भारतीय संसद के गठन व संरचना को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

लोकसभा एवं राज्यसभा के गठन व संरचना को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– भारतीय संसद का गठन व संरचना– किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के तीन अंग होते हैं–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनु. 79 में किया गया है। 'भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे।

(अ) लोकसभा–लोकसभा के गठन व संरचना का वर्णन निम्नलिखित बिन्दुओं के अंर्तगत प्रस्तुत है–

(क) सदस्य संख्या– संघीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य 552 निर्धारित की गई है। जिसमें 530 सदस्य राज्यों से व 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से तथा 2 सदस्य एग्लो इंडियन होते है।

(ख) निर्वाचन – लोकसभा के सदस्यों के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होते है।

(ग) कार्यकाल –लोकसभा एक अस्थायी सदन है। मूल रूप से इसका कार्यकाल 5 वर्ष है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकते है।

(घ) सदस्यों की योग्यताएँ– लघुरात्मक प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देंखे।

(ङ) पदाधिकारी – लोकसभा सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक का संचालन करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कार्य करता है।

(ब) राज्यसभा– राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन है।

गठन व संरचना निम्न है–

(1) सदस्य संख्या– अनु.80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रावधान हैं। राज्यसभा के कुल 250 सदस्य होते है जिसमें से 238 सदस्य राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा शेष 12 सदस्यों को जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो, राष्ट्रपति मनोनीत करता है।

(2) निर्वाचन –राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा नहीं होता है। अपितु अनु. 80(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है।

(3) कार्यकाल–राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात् अवकाश ग्रहण करते हैं व 1/3 नवीन सदस्य पद ग्रहण करते है।

(4) सदस्यों की योग्यताएँ–राज्यसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है।

(5) पदाधिकारी –भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जो राज्यसभा की बैठकों व अन्य गतिविधियों का संचालन करता है।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न–2 भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– **(1) साधारण विधेयक का प्रस्तुतीकरण–** कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते है। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह दो तरह का होता है एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक।

(2) विधेयक पहले सदन में – जिस सदन में विधेयक रखा गया है, उसमें उसे पारित करने के लिए तीन वाचन की प्रक्रिया से गुजरना होता है–

(अ) प्रथम वाचन– नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खडे होकर प्रस्ताव पेश करता है। किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है।

(ब) द्वितीय वाचन–द्वितीय वाचन में सामान्यतः विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाता है जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है।

(स) तृतीय वाचन–इसके पश्चात् विधेयक में आवश्यक शाब्दिक एवं औपचारिक संशोधन किये जाते है एवं अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो तो वह सदन से पारित समझा जायेगा।

(3) विधेयक दूसरे सदन में– पहले सदन में विधेयक के पारित होने के बाद उसे पारित करने के लिए दुसरे सदन में ष्जा जाता है।

(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक– दोनों सदनों में साधरण विधेयक पर मतभेद की स्थिति का समाधान करने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आमंत्रित करता है। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

(5) विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति – दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर विधेयक कानून बन जाता है।

प्रश्न–3 राज्यसभा और लोकसभा की किन्हीं पाँच बिन्दुओं के आधार तुलना कीजिए।

उत्तर– **राज्यसभा–**

(1) राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है।

(2) यह राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

(3) राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षो का होता है, प्रत्येक दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते है एवं उतने ही नवनिर्वाचित भी हो जाते है।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

(5) राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर खुली मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

लोकसभा–

(1) लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते है परन्तु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है।

(2) यह समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

(3) लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है।

(4) लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है।

(5) मंत्रीपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उतरदायी होती है।

प्रश्न–4 ''भारतीय संसद दुनियाँ की शक्तिशाली विधायिकाओं में से एक है।'' इसके कार्य एवं शक्तियों की समीक्षा कीजिए ।

उत्तर– भारतीय संसद की शक्तियाँ व कार्य–

भारतीय संसद दुनियाँ की शक्तिशाली विधायिकाओं में से एक है,क्योंकि विधि निर्माण ,संविधान संशोधन, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा वितीय क्षेत्र में इसकी शक्तियाँ सर्वोच्च है यथा–

(1) विधायी या विधि निर्माण संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ–संसद भारत की व्यवस्थापिका है। अतः इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण का है संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों में से किसी भी विषय पर संसद विधान बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पर भी विधि निर्माण की शक्ति संसद को ही प्राप्त है।

(2) धन विधेयक पारित करना –संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक पारित करना है । संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण लगाती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

(3) संविधान संशोधन का कार्य–भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से करना होता है। परन्तु संघीय महत्व के कुछ संशोधनों के लिए संसद के दोनो सदनों के दो तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

(4) कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य–कार्यपालिका के दिन– प्रतिदिन के कार्यो में नियंत्रण करने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है – जैसे प्रश्न पूछ कर, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा। कार्यपालिका पर नियंत्रण की सबसे बडी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है वह है – विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। विश्वास मत के पारित न होने और अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के परिणाम स्वरूप मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटना होता है।

पाठ–3

न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन

1. भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौनसी व्यवस्था प्रचलित है?

उत्तर – कॉलेजियम व्यवस्था, मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश,

2. NJAC का विस्तृत रूप क्या है?

उत्तर :– राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग।

3. न्यायाधीशों को उनके पद से किन आधारों पर हटाया जा सकता है?

उत्तर :– 1. साबित कदाचार 2. शारीरिक अक्षमता

4. भारतीय संविधान में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है?

उत्तर :– एकीकृत पिरामिड के समान।

5. भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है?

उत्तर :– जनहित याचिका।

6. जनहित याचिकाओं का प्रारम्भ किये जाने का श्रेय किसे दिया जाता है?

उत्तर :– न्यायाधीश पी.एन. भगवती।

7. जनहित याचिकाओं की शुरूआत कब हुई?

उत्तर :– 1979

8. भारत में अपील का अंतिम न्यायालय कौनसा है?

उत्तर :– सर्वोच्च न्यायालय।

9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की शक्ति किसे प्राप्त है?

उत्तर :– सर्वोच्च न्यायालय को।

लघुतरात्मक प्रश्न –

1. मौलिक / प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– ऐसे मामले जिनकी सुनवायी केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते है जैसेः–
(क) संघीय विवाद जिनमें केन्द्र–राज्य एवं राज्य–राज्य के मध्य के विवाद शामिल है।
(ख) राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद शामिल है।

2. रिट संबंधी/समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या है ?

उत्तर :– मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ही ऐसे मामलों की सुनवायी कर सकते हैं, इसलिए इसे समवर्ती क्षेत्राधिकार कहा जाता है इसके तहत दोनों ही न्यायालय पाँच प्रकार की रिट/आदेश (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा) जारी करके कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकते है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का महत्व समझाइये।

उत्तर :– इसके अनुसार राष्ट्रपति "लोकहित" या "संविधान की व्याख्या" से संबंधित विषय पर सर्वोच्च न्याायलय से सलाह मांग सकता है इस अधिकार की दो उपयोगिताऐं हैः–
(क) इससे कार्यपालिका को किसी महत्वपूर्ण विषय पर कार्यवाही करने से पूर्व अदालत की कानूनी राय जानने का अवसर मिल जाता है
(ख) सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन का अवसर मिल जाता है

4. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को समझाइये।

उत्तर :– सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम एवं उच्चतम न्यायालय है कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय दायर मुकदमें पर पुनर्विचार करते हुए कानूनी मुद्दों की दुबारा जाँच करता है इसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत भी रख सकता है या उसके निर्णय को बदल भी सकता है

शेखावाटी मिशन–100

5. "न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर है" व्याख्या कीजिए

उत्तर :– मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है संविधान में ऐसी दो विधियों का वर्णन है जिनसे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके :–

(क) अनुच्छेद 32 :– इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित करता है। यहाँ न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाती है ।

(ख) अनुच्छेद 13 :– यह संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण होने से बचाता है यहाँ न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के व्याख्याकार की भूमिका निभाती है ।

6. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया समझाइए ।

उत्तर – भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह से करता है। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश एवं चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीशों के इस समूह की भूमिका का प्रभाव अधिक है जो सामूहिकता के सिद्धांत की स्थापना करता है।

7. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संगठन समझाइए ।

उत्तर – राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 के तहत इसकी स्थापना की गई । इसमें अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायधीश, सदस्यों में दो वरिष्ठतम न्यायधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एवं दो प्रबुद्ध/विख्यात व्यक्ति होंगे ।

उपर्युक्त दो प्रबुद्ध/विख्यात व्यक्तियों का चयन एक समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री , भारत का मुख्य न्यायधीश और नेता प्रतिपक्ष/बसे बडे विपक्षीदल का नेता सहित तीन सदस्य शामिल होंगे।

8. न्यायिक सक्रियता और जनहति याचिका परस्पर जुडी हैं । स्पष्ट कीजिए

उत्तर – हाल ही के वर्षों में जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने समाज के गरीब व शोषित लोगों को न्याय प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है । इसके तहत सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों में बिना फीस एवं निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा की गई शिकायत की सुनवाई कर न्यायपालिका आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कार्यपालिका को आदेशित करती है जनहित में दायर मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण न्यायिक सक्रियता कहलाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता और जनहति याचिका परस्पर जुड़ी है ।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु क्या–क्या प्रावधान किये गये है ? व्याख्या कीजिए।

उत्तर :– भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं जिनमें से प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं–

क. न्यायधीशों की नियुक्ति के मामलें में संसद/विधायिका को शामिल नहीं किया गया है ताकि न्यायपालिका को दलगत राजनीति से दूर रखा जा सके।

ख. नियुक्ति का आधार योग्यता व अनुभव को बनाया गया है।

ग. न्यायधीशों को लम्बा व सुरक्षित कार्यकाल प्रदान किया गया है।

घ. न्यायधीशों को उनके पद से हटाने के लिए एक कठिन प्रक्रिया (महाभियोग) का प्रावधान किया गया है।

ड. न्यायधीशों के कार्यों एवं निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है।

च. न्यायालय की अवमानना के दोषी व्यक्ति को न्यायालय दण्डित करने की शक्ति रखता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों व शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर :– लघुतरात्मक प्रश्नों में 1 से 5 के उत्तर देखें।

शेखावाटी मिशन–100

इकाई – 3
भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां
जातिवाद एवं संप्रदायवाद

1. जाति वाद को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था की?

उत्तर :– दलित वर्गो के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था।

2. पूना समझौता/पैक्ट (1932) किस–किस के मध्य हुआ ?

उत्तर :– महात्मा गाँधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर

3. "जाति के लिए राजनीति का महत्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है" कथन किसका है ?

उत्तर :– मोरिस जॉन्स का।

4. जाति क्या है ?

उत्तर :– जाति पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित एक बंद वर्ग है

5. "जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है" कथन किसका है ?

उत्तर :– जयप्रकाश नारायण ।

6. भारत में किन चुनावों में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी रहता है ?

उत्तर :– पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में।

7. किन–किन राज्यों में वर्तमान में जाति के आधार पर आरक्षण की मांग उठ रही है।

उत्तर :– हरियाणा(जाट), राजस्थान(गुर्जर), गुजरात(पाटीदार)

8. जातिवाद को कम करने वाले कारक कौन–कौन से है ?

उत्तर :– शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगीकरण, लोकतंत्र, आधुनिकीकरण आदि।

9. भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या कब शुरू हुई ?

उत्तर :– ब्रिटिश शासन काल में।

10. गोधरा (गुजरात) में सांप्रदायिक घटना कब हुई ?

उत्तर :– 27 फरवरी 2002

लघुतरात्मक प्रश्न –

1. भारत में "निर्णय प्रक्रिया" में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– भारत में जाति आधारित संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करवाने एवं अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु विभिन्न प्रकार से शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते है। जैसे आरक्षण प्राप्त जातियां आरक्षण की समय सीमा बढाने हेतु और कुछ जातियां अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल कराने हेतु प्रयत्नशील है।

2. "मंत्रीमंडल निर्माण" में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाये रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रीमंडल का निर्माण करते समय जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखते है तथा मंत्रीमंडल में सभी जातीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते है।

3. जातीय संगठनों की दबाव समूह के रूप में भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत हुए है। ये संगठन अपने हित में निर्णय करवाने हेतु या अपने हितों के विरूद्ध निर्णयों को रोकने हैतु धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं हिंसा के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते है।

4. "वोट बैंक की राजनीति" से आप क्या समझते है ?

उत्तर :– जब कोई राजनीतिक दल या नेता किसी जाति या संप्रदाय की उचित या अनुचित मांगों का समर्थन करे व उन्हे प्रोत्साहित करे तो इसे वोट बैंक की राजनीति कहते है।

शेखावाटी मिशन–100

5. भारतीय चुनावों में जाति की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– (क) राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय करना।

(ख) जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार करना।

(ग) चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लेना।

9. सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य क्या होता है ?

उत्तर :– शासन पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनैतिक अधिकर प्राप्त करना।

10. धार्मिक आधार पर निर्मित चार राजनैतिक दलों के नाम लिखिए।

उत्तर :– हिंदु महासभा, अकाली दल, जमात–ए–इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।

11. सांप्रदायिकता के स्वरूप कौन–कौन से हैं ? इनकी प्रकृति भी समझाइये।

उत्तर :– सांप्रदायिकता के दो रूप हैं –

(क) बहुसंख्यक सांप्रदायिकता

(ख) अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता

बहुसंख्यक सांप्रदायिकता स्वयं को छद्म राष्ट्रवाद के रूप में तथा अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता स्वयं को अलगाववाद के रूप में प्रस्तुत करती है।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को सविस्तार समझाइये।

उत्तर :– लघुतरात्मक प्रश्नों में 1,2,3 देखें।

2. जातिगत राजनीति की 4 विशेषताऐं बताइये।

उत्तर :– क. जातिगत संगठनों की राजनीतिक महत्वकांक्षा बढ़ी है।

ख. शिक्षा, शहरीकरण, लोकतंत्र के बावजूद भी जातिवादी भावनाएं सशक्त हुई है।

ग. जाति व राजनीति के संबंध सदा एक जैसे नहीं रहते है।

घ. जाति के राजनीतिकरण के साथ–साथ राजनीति का जातिकरण भी हो रहा है

3. जातिगत राजनीति के 4 नकारात्मक प्रभाव बताइये।

उत्तर :– क. जातीय संघर्ष एवं परस्पर द्वेष की भावना का विस्तार हुआ है।

ख. जातिवाद की भावना के कारण राष्ट्रभक्ति एवं एकता व भाईचारे की भावना कमजोर हुई है।

ग. अल्पसंख्यक जातियों एवं समुदायों में असुरक्षा की भावना का विकास हुआ है।

घ. इससे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिला है।

4. जातिगत राजनीति के कोई चार सकारात्मक प्रभाव बताइये।

उत्तर :– क. इसके कारण राजनीति में जनभागीदारी में वृद्धि हुई है।

ख. सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से कमजोर जातियों के महत्व में भी वृद्धि हुई है।

ग. समाज में सांस्कृतिक एकता बढ़ी है।

घ. जातीयों के पदसोपानिक संबंध (ऊँच–नीच) समाप्त हुए है जो सामाजिक समानता को बढ़ाते है।

5. मिलान कीजिए

घटना	वर्ष
क. बंगाल विभाजन (कर्जन)	1905
ख. मुस्लिम लीग की स्थापना	1906
ग. सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ	1909
घ. द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन(जिन्ना)	1940
ड. भारत का विभाजन (सांप्रदायिक)	1947

उत्तर :– ये घटनायें इसी क्रम में सुव्यवस्थित है।

शेखावाटी मिशन–100

6. भारत में सांप्रदायिकता के कोई पांच कारण लिखिए।

उत्तर :– क. भारत विभाजन के समय हिंसा–दंगे, हत्यायें एवं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की कटु स्मृतियां।

ख. राजनीतिक दलों द्वारा निहीत स्वार्थो के कारण सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना।

ग. भारतीय मुसलमानों का आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना।

घ. पाकिस्तान द्वारा किया जाने वाल दुष्प्रचार एवं षड्यंत्र।

ड. वोट बैंक की राजनीति।

7. साम्प्रदायिकता के 4 दुष्परिणाम लिखिए।

उत्तर :– क. इससे आपसी द्वेष, अविश्वास व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है।

ख. सांप्रदायिक दंगो के कारण जन व धन दोनों की हानि हुई है

ग. सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के औद्योगिक व व्यावसायिक विकास में बहुत बड़ी बाधक है

घ. इससे अलगाव की भावना बढ़ती है जो राट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है

8. साम्प्रदायिकता को दूर करने के कोई पांच उपाय लिखिए।

उत्तर :– क. धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक समुदाय को विशेष सुविधायें न दी जाये।

ख. चुनावी राजनीति एवं चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने से रोकने हैतु कठोर कानूनों का निर्माण व उनका क्रियान्वन किया जाये।

ग. साम्प्रदायिक आधार पर उठने वाली प्रतिनिधित्व की मांगो को पूर्णतः नकारा जाये।

घ. धर्म के आधार पर राजनैतिक दलों का गठन न हो और धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगे।

ड़. शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव के आदर्शों का समावेश किया जाये।

9. "सच्चर कमेटी" क्या है ? इसने क्या सुझाव दिये ?

उत्तर :– भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने एवं उसमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सेवानिवृत न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसे सच्चर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने मुसलमानों के कल्याण व विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया जिसमें सर्व शिक्षा अभियान एवं मुस्लिम बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाओं का सुझाव प्रमुख थे।

शेखावाटी मिशन–100

आंतकवाद, राजनीति का अपराधीकरण व भ्रष्टाचार

1. "आतंकवाद एक विभ्रम है" कथन किसका है ?

उत्तर :– ओ दिमेरस।

2. आतंकवाद को किन आधारों पर समर्थन मिलता है?

उत्तर :– धर्म, जाति, नस्ल व क्षेत्र के आधार पर।

3. आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या है?

उत्तर :– वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना।

4. 9/11 की आतंकवादी की घटना कहाँ हुई?

उत्तर :– संयुक्त राज्य अमेरिका में।

5. "ए थ्योरी ऑफ कॉन्फलिक्ट" किसकी रचना है?

उत्तर :– बी क्रोजियर।

6. UAPA का पुरा नाम लिखिए।

उत्तर :– अनाधिकृत गतिविधि निवारक अधिनिमय।

7. "पीपुल्सवार ग्रुप" क्या है?

उत्तर :– आंध्रप्रदेश में सक्रिय आतंकवादी गुट।

8. माऊ– माऊ क्या है?

उत्तर :– केन्या का आतंकवादी गुट।

9. भारतीय राजनीति के आपराधिकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है?

उत्तर :– राजनीतिक दलों द्वारा येन केन प्रकारेण सता प्राप्त करने की लालसा।

10. "दागी मंत्री" से क्या आशय है?

उत्तर :– ऐसे मंत्री जो आपराधिक पृष्ठभूमि के है।

11. NOTA का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर :– NONE OF THE ABOVE (उपर्युक्त में से कोई नही)

12. भ्रष्टाचार निरोधक कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था की है?

उत्तर :– "भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो" की।

13. भ्रष्टाचार का आरम्भिक केन्द्र क्या है?

उत्तर :– औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला चन्दा।

लघुतरात्मक प्रश्न –

1. आतंकवाद को बढावा देने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन–कौनसी है ?

उत्तर :– (क) नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां

(ख) हथियारों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2. आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व लिखिए।

उत्तर :– (क) कर्म द्वारा प्रचार (ख) अभित्रास (ग) उकसाना (घ) अस्त व्यस्तता व अराजकता (ड.) संघर्ष

3. किन्ही दो आतंकवादी गुटों की सफलता का उल्लेख कीजिए।

उत्तर :– आतंकवादियों को केवल औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध सफलता प्राप्त हुई है जैसे–

(क) माउ–माउ को केन्या में ब्रिटिश शासन के विरूद्ध

(ख) एफ एल एन को अल्जीरिया में फ्रांसिसी शासन के विरूद्ध

4. राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :– राजनीति के अपराधीकरण के दो अर्थ है–

(क) संकीर्ण अर्थ – अपराधियों का विधानसभा और संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश व हस्तक्षेप।

(ख) व्यापक अर्थ – अपराधियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति व शासन को प्रभावित करना जिसमें धनबल व बाहुबल से राजनीतिक दलों की मदद करना शामिल है।

5. राजनीति के अपराधीकरण को रोकने हेतु "एन.एन.बोहरा" समिति ने क्या–क्या सुझाव दिये ?

उत्तर :– (क) सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना

(ख) जनता की ईमानदारी व सक्रिय चुनावी भागीदारी

(ग) न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग व नौकरशाही की निष्पक्षता सुनिश्चित करना

6. भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले किन क्षेत्रों से संबंधित हैं ?

उत्तर :– खरीद, अनुदान, निर्माण, लाईसेंस–परमिट आवंटन, ऋण, नियुक्ति एवं स्थानांतरण।

7. भ्रष्टाचार क्या है ?

उत्तर :– जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से परे जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाये तथा बदले में धन या सुविधायें प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचायें यह संपूर्ण प्रक्रिया/व्यवस्था भ्रष्टाचार कहलाती है।

8. पृथकतावादी/अलगाववादी आतंकवाद क्या है ? यह भारत के किन किन राज्यों में व्याप्त है ?

उत्तर :– आतंकवाद की वह प्रकृति जो किसी राज्य को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहती है पृथकतावादी श्रेणी का आतंकवाद कहलाता है इसे धार्मिक आधार पर समर्थन प्राप्त होता है पंजाब और जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद इसी श्रेणी का है।

9. नक्सलवाद/माओवाद क्या है ? इससे भारत के कौन–कौन से राज्य प्रभावित हैं ?

उत्तर :– आतंकवाद का वह स्वरूप जो विद्यमान शासन व्यवस्था में आमूल–चुल परिवर्तन चाहता है। ये पृथकववाद से भिन्न है। इसकी शुरूआत नक्सलबाड़ी (प0 बंगाल) से होने के कारण इसे नक्सलवाद तथा माओं की विचारधारा से प्रेरित होने के कारण हसे माओवाद कहा जाता है इससे प0 बंगाल, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश आदि राज्य प्रभावित हैं।

10. उग्रवाद क्या है ? इससे प्रभावित राज्य कौन–कौन से हैं ?

उत्तर :– यह आतंकवाद का वह स्वरूप है जिसमें किसी आतंकवादी गुट के द्वारा अन्य जनजाति या समुदाय को निशाना बनाया जाता है इससे पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड प्रभावित हैं।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारत में आतंकवाद पर लेख लिखिए।

उत्तर :– लघुतरात्मक प्रश्नों 8,9,10 में इसकी व्याख्या की गई है।

2. आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभाव लिखिए।

उत्तर :– क. इससे आतंकवादी गुटों के निर्माण को प्रेरणा मिलती है

ख. आतंकवादियों को लोकप्रियता प्राप्त होती है

ग. इससे आतंकवादी गुटों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिससे आतंकवादी घटनाओं की वृद्धि होती है

घ. इससे प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

ङ़. इससे आतंकवादियों को अपनी राजनीतिक मांगे रखने का मंच प्राप्त हो जाता है

3. मिलान कीजिए

आतंकवादी गुट	**प्रभावित देश**
क. लिट्टे/LTTE	श्रीलंका
ख. तालिबान	अफगानिस्तान
ग. ISIS	ईराक व सीरिया
घ. एक्शन डाइरेक्टो	फ्रांस
ड. लाल गुट सेना	इटली

उत्तर :– ये इसी क्रम में सुमेलित है

शेखावाटी मिशन–100

4. हाल ही में चुनावों में भ्रष्टाचार व अपराधीकरण को कम करने के लिए क्या–क्या सुधार किये गये है ?

उत्तर :– क. ईवीएम मशीनों का प्रयोग

ख. संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी

ग. निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

घ. चुनावी आचार संहिता को लागू करना

5. राजनीति के अपराधीकरण के प्रमुख 5 कारण बताइये।

उत्तर :– क. दलीय राजनीति एवं सता प्राप्ति की अत्यधिक लालसा।

ख. पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों व अपराधियों में सांठगांठ।

ग. आपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा व स्वीकार्यता।

घ. कानूनों को प्रभावशाली रूप में लागू नहीं करना।

ड़. न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां।

6. राजनीति के अपराधिकरण को रोकने के उपाय लिखिए।

उत्तर :– क. राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करना।

ख. अपराधियों को टिकट देने वाले दलों पर प्रतिबंध लगाना।

ग. निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष व पारदर्शी गठन।

घ. राजनीति में सक्रिय अपराधियों के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु "फास्ट ट्रेक" न्यायालयों की स्थापना।

ड़. नोटा(NOTA) के साथ–साथ अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था।

7. भ्रष्टाचार के कोई 4 परिणाम लिखिए।

उत्तर :– क. सार्वजनिक निर्माण कार्यों का घटिया स्तर।

ख. योग्य व निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाना।

ग. समाज में आर्थिक विषमता व काले धन में वृद्धि।

घ. गरीबों के जीवन व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव।

8. भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सुझाव दीजिए।

उत्तर :– क. सरकारी निर्णयों में अधिकाधिक पारदर्शिता होनी चाहिए।

ख. नागरिकों को सरकारी निर्णयों व गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए।

ग. राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरह जाँच पड़ताल होनी चाहिए।

घ. भ्रष्टाचार निरोधक कानून, बेनामी सौदा अधिनियम 1988 को दृढ़ता से लागू करना।

ड़. दोषी अधिकारियों, कार्मिकों पर कठोर कार्यवाही व कठोर दण्ड दिये जाने की आवश्यकता है।

शेखावाटी मिशन–100

1. भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरूआत कब से हुई?

उत्तरः– चतुर्थ आम चुनाव (1967) से।

2. "जनता दल" का गठन कब हुआ?

उत्तर :– 1977 में।

3. जनता दल की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे?

उत्तर :– श्री मोरारजी देसाई

4. जनता दल का विघटन क्यों एवं कब हुआ?

उत्तर :– दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर 1980 में।

5. भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे?

उत्तर – श्री मनमोहन सिंह

6. भारत में कौनसी दलीय व्यवस्था है?

उत्तर – बहुदलीय व्यवस्था।

7. NDA/राजग का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर :– राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance)

8. UPA/संप्रग का पूरा नाम लिखिए।

उत्तर :– संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (United Progressive Alliance)

9. भारतीय राजनीति में गठबंधन का मुख्य दौर माना जाता है?

उत्तर :– 11वी से 15वी लोकसभा जिनमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।(1989 से 2014)

लघुतरात्मक प्रश्न –

1. "गठबंधन की राजनीति" से आप क्या समझते है ?

उत्तर :– लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में दो या दो से अधिक दल मिलकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार का निर्माण करते है, इसे ही गठबंधन की राजनीति कहा जाता है।

2. गठबंधन कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर :– गठबंधन दो प्रकार के होते हैं–

(क) वे गठबंधन जो चुनाव से पहले बनाये जाते है जैसे एनडीए, यूपीए।

(ख) चुनाव के पश्चात् सत्ता प्राप्ति के लिए बनाये जाने वाले गठबंधन।

3. वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन–कौन से गठबंधन हैं ? उनमें मुख्य दल व नेता कौन–कौन हैं ?

उत्तर :– भारतीय राजनीति में वर्तमान में तीन मुख्य गठबंधन हैं–

1. एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) – इसमें मुख्य राजनैतिक दल भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) है वर्तमान में इसी गठबंधन की सरकार है इसके नेता श्री नरेन्द्र मोदी है।

2. यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) – इसमें मुख्य दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी नेता श्रीमती सोनिया गाँधी है वर्ष 2004 से 2014 तक श्री मनमोहन सिंह जी इसी गठबंधन से प्रधानमंत्री रहे।

3. तीसरा मोर्चा/वामपंथी गठबंधन – इसमें वामपंथी राजनैतिक दल सीपीआई व सीपीएम शामिल हैं इसके नेता श्री डी. राजा व श्री सीताराम येचुरी हैं ।

शेखावाटी मिशन–100

4. गठबंधन सरकारे बनने के क्या – क्या कारण हैं ?

उत्तर :– 1. भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाना।

2. धर्म, जाति, संप्रदाय आदि की विभिन्नताओं के कारण वर्गीय हितों पर अनेक राजनैतिक दलों का गठन।

निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारत में गठबंधन की राजनीति की विशेषताऐं बताइये।

उत्तर :– क. प्रत्येक गठबंधन में प्रधान दल और कुछ छोटें दल होते हैं।

ख. गठबंधन में विचारधारा की समानता का अभाव पाया जाता है गठबंधन केवल सता प्राप्ति के लिए बनते है।

ग. गठबंधन बनते व टूटते रहते हैं अर्थात् स्थायित्व का अभाव होता है।

घ. गठबंधन दल व सिद्धांतों पर नहीं नेताओं के आधार पर बनाये जाते है।

2. गठबंधन की राजनीति के कोई 4 लाभ लिखिए।

उत्तर :– क. इससे शासन की निरंकुशता समाप्त हो जाती है।

ख. इससे अलग–अलग दलों के अधिक योग्य व्यक्तियों के योगदान का देश को लाभ मिलता है।

ग. गठबंधन से निर्मित मंत्रीपरिषद् को व्यापक जनमत का समर्थन प्राप्त होता है।

घ. इससे एक शक्तिशाली विपक्ष का निर्माण होता है।

3. गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक पक्ष को समझाइये।

उत्तर :– क. इससे कमजोर एवं अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है।

ख. इससे प्रधानमंत्री की भूमिका और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना में कमी व सीमितता आ जाती है।

ग. इसमें क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता है जो छोटे–छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

घ. इससे सरकार के कार्यों में स्पष्टता और विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव दिखाई देता है।

ङ. इसमें सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव पाया जाता है।

च. इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है।

शेखावाटी मिशन–100

इकाई – 4

भारत की विदेश नीति एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ

भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताऐं – गुट निरपेक्षता

1. भारतीय विदेशी नीति का जनक किसे कहा जाता है ?

उत्तरः– प.जवाहर लाल नेहरू को।

2. पंचशील सिद्धान्तों का सम्बन्ध किन दो देशों से हैं ?

उत्तरः– भारत व चीन से

3. बांडुग सम्मलेन कब हुआ

उत्तरः– वर्ष 1955 में

4. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सस्थांपक कौन थे ?

उत्तरः– नेहरू, नासिर और टीटो

5. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में स्थाई सदस्यता की मांग कर रखी है ?

उत्तरः– सुरक्षा परिषद्

6. यूएनओ का पूरा नाम बताईए।

उत्तरः– यूनाइटेड नेशन्स ऑगेलाइजेशन (संयुक्त राष्ट संघ)

7. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरूआत किस सम्मेलन से हुई ?

उत्तरः– बेलग्रेड सम्मेलन 1961 से

8. भारत व पाकिस्थान के मध्य सिन्धु जल समझौता कब हुआ ?

उत्तरः– 1960 ईस्वी में

9. 169एनक्लेव विवाद किन दो देशो के मध्य है ?

उत्तरः– भारत व बाग्लादेश के मध्य

10. सोवियत संघ का विघटन कब हुआ ?

उत्तरः– 1991 में

11. भारत ने ऑपरेशन नीर किस देश के लिए चलाया ?

उत्तरः– मालदीव के लिए

12. पंचशील सिद्वातों की घोषणाा कब हुई ?

उत्तरः– 29 अप्रैल 1954 को

13. भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तरः– शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।

14. गुट निरपेक्षता का अर्थ बताईए ।

उत्तरः– विश्व के किसी भी गुट के साथ न जुड़कर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना ।

15. भारत की विदेश नीति के अक्ष में गुटपेक्षता को अपनाने का प्रमुख कारण क्या है ?

उत्तरः– भारत किसी एक गुट से जुड़कर विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का पक्षधर नहीं था इसलिए गुट निरपेक्षता को अपनाया।

16. वर्तमान में भारत की आतंकवाद के प्रति क्या नीति है?

उत्तरः– आतंकवाद के प्रति जिरो टोलरेंस / शून्य सहयता की नीति।

17. गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र कौनसे हैं ?

उत्तरः– भारत, युगोस्लाविया और मिस्त्र

18. बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ?

उत्तरः– 16 दिसम्बर 1971 को

19. सह अस्तित्व का क्या भावार्थ है?

उत्तरः– जीओ और जीने दो।

20. भारत में गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया?

उत्तरः— 1983 में (नई दिल्ली)

21. भारत ने व्यापक अणु प्रसार निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किये ?

उत्तरः— अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण।

22. भारत की विदेश नीति में लुक ईस्ट नीति अब किसमें बदल गई?

उत्तरः— एक्ट ईस्ट नीति में।

23. मध्य पूर्व के प्रति भारतीय विदेश नीति की समीक्षा कीजिए ।

उत्तरः— भारत का मध्य पूर्व के देशो से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है।

लधुरात्मक प्रश्न –

प्रश्नः—1 पंचशील के सिद्धान्तों पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तरः— पंचशील सिद्धान्तों का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के प्रधानमंत्री (चाउ एन लाई व नेहरू) के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर करके किया। इसमें पांच सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

1. एक दूसरे देश की अखण्डता और सर्वेच्च सता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना।
2. अनाक्रमण।
3. अहस्तक्षेप— एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
4. समानता
5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व

प्रश्नः—2 उपनिवेशवाद क्या है?

उत्तरः— विश्व के किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र या देश को अपने अधीन करना उपनिवेशवाद कहलाता है भारत हमेशा से इसका विरोधी रहा है।

प्रश्नः—3 रंगभेद से आप क्या समझते है?

उत्तरः— सरकार द्वारा अपने नागरिको के लिए रंग के आधार पर भेदभावपूर्ण ढ़ंग से कानून लागू करना तथा रंग के आधार पर व्यक्तियों में अधिकारों का भेदभाव करना रंगभेद कहलाता है। इसका आधार एक समूह विशेष को ज्यादा अधिकार देना होता है।

प्रश्नः—4 गुट निरपेक्षता का अर्थ बताईए।

उत्तरः— किसी भी गुट में शामिल न होते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुऐ, स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। यह शक्ति गुटों से अलग रहने की सक्रिय विदेश नीति है। यह सकारात्मक नीति है।

प्रश्नः—5 सह—अस्तित्व के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

उत्तरः— भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल देती है। भारत की यह धारणा रही है कि विश्व में सभी देशों के साथ हमारे रिश्ते भी इसी नीति पर आधारित हैं। 1956 का स्वेज नहर सकंट, 1967 का अरब ईजराईल युद्ध, 1960 का सिन्धु जल समझौता, 1965 का भारत पाक युद्ध, हमने इस नीति को कभी नहीं छोड़ा।

निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्नः—1 भारत की विदेश नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तरः— लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर देखें।

शेखावाटी मिशन—100

संयुक्त राष्ट्र संघ– संगठन एवं विश्व शांति में योगदान

1. संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) की स्थापना कब हुई ?
उत्तर – 24 अक्टूम्बर 1945

2. संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है ?
उत्तर– 24 अक्टूम्बर

3. संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है ?
उत्तर– 51 राष्ट्र

4. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है?
उत्तर– हैग (नीदरलैण्ड)

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में भारत के न्यायाधीश कौन है?
उत्तर– जस्टिस दलबीर भंडारी

6. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के पांच स्थाई देशों के नाम बताइये ?
उत्तर – अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस।

7. सुरक्षा परिषद् में कितने अस्थाई सदस्य होते है?
उत्तर– 10

8. संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में कितने अनुच्छेद है?
उत्तर– 111

9. संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है?
उत्तर– 6

10. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर– सुरक्षा परिषद् की सिफारिश के आधार पर महासभा

11. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या है?
उत्तर– विश्व में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना

12. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है?
उत्तर – न्यूयॉर्क

13. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते है?
उत्तर– 15

14. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
उत्तर– 9 वर्ष

15. महासभा के प्रथम सभापति कौन थे?
उत्तर– बेल्जियम के मिस्टर पाल स्पूक

16. वर्तमान मे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ?
उत्तर – एन्टोनियो गुटरेस (पुर्तगाल)

17. संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कब और कहां हुई ?
उत्तर– 10 जून 1946 को लंदन में

18. संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे दी जाती है ?
उत्तर– सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा

19. महासभा में कोई राष्ट्र अपने अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है ?
उत्तर– 5 (नोट – मतदान का अधिकार केवल एक ही प्रतिनिधि को प्राप्त होता है)

20. पूरा नाम लिखो ?
(i) WHO (ii) ILO (iii) UNESCO
उत्तर– (i) विश्व स्वास्थ्य संगठन (ii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (iii) संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन

लघुरात्मक प्रश्न :–

प्रश्न–1 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य बताईये ?
उत्तर – निम्नलिखित उद्देश्य हैं – (i) विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाये रखना (ii) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं मानवीय किसी भी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाना (iii) समान अधिकारो को प्राप्त करने के लिए आदर एवं मित्रतापूर्वक संबंध बनाना।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न–2 वीटो किसे कहते है?

उत्तर– वीटो का शाब्दिक अर्थ है– ''मै मना करता हूँ।'' यह सुरक्षा परिषद् के पांच स्थाई सदस्य राष्ट्रों का एक ऐसा अधिकार है कि अगर वे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असहमत हो जाते हैं तो उसे अस्थाई सदस्यों की सहमति के बाद भी अस्वीकार कर दिया जाता है।

प्रश्न–3 वर्तमान परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक बनाने हैतु सुझाव दिजिए ?

उत्तर– (i) संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच स्थाई सदस्यों के स्थान पर 15 स्थाई सदस्य हो।

(ii) भारत, ब्राजील, जर्मनी व जापान को भी स्थाई सदस्य बनाया जाये।

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ के कोष में अभिवृद्धि की जानी चाहिए जिससे वह विकास के कार्यो में अधिक भागीदारी निभा सके।

(iv) पर्यावरण व आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्याओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए।

प्रश्न–4 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन व कार्यो के बारे में बताईए ?

उत्तर– महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का महासभा में एक वोट होता है। महासभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को एक वर्ष के लिए सभापत्ति चुनते हैं। अध्यक्ष की सहायता के लिए महासभा में 17 उपाध्यक्ष होते है। महासभा का सत्र सितम्बर माह के तीसरे मंगलवार को हर वर्ष बुलाया जाता है। महासभा के बहुमत सदस्यो की प्रार्थना पर इसका विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।

महासभा के कार्य :–

(i) अन्तराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी मामलो पर विचार–विमर्श करना।

(ii) निरीक्षण संबंधित कार्य।

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना।

(iv) चुनाव संबंधी कार्य।

(v) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करना।

प्रश्न–5 सुरक्षा परिषद् पर संक्षिप्त टिप्पणी किजिए ।

उत्तर– सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी परिषद् है। इसके 5 स्थाई व 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। अस्थाई सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद् विश्व शांति व सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षक है इसे विश्व शांति और सुरक्षा बनाये रखने का विशेष उत्तरदायित्व सौपा गया है सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदसयों के पास वीटो पावर होता है इसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में किसी भी कार्यवाही के लिए पाँचों स्थाई सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है । चीन, रूस, फ्राँस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन इसके पाँच स्थाई सदस्य राष्ट्र हैं।

प्रश्न–6 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन व उपयोगिता बताइये?

उत्तर– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा प्रमुख अंग है। इसका मुख्यालय हैग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अन्तराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होते हैं।

संगठन– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है तथा हर तीन वर्ष बाद 5 न्यायधीश सेवानिवृत हो जाते हैं। न्यायधीश पुनः निर्वाचित भी सकते हैं। इसके अलावा कुछ तदर्थ न्यायधीश भी होते हैं व अन्तर्राष्ट्रीय कानून में मान्य योग्यता के जानकर व अपने अपने देशो की उच्च अदालतों में नियुक्ति में आवश्यक योग्यता वाले होते हैं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अब तक विश्व के बहुत से मामलों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने में कामयाब रहा है।

प्रश्न–7 न्यासपरिषद् क्या कार्य करती है?

उत्तर – संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अभिकरणों में न्यासपरिषद् भी एक है यह एक अधीनस्थ अंग है क्योंकि महासभा के सहायक अंग के रूप में यह असामरिक ट्रस्ट भू–क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण तथा सामरिक क्षेत्रों के मामले में सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में कार्य करती है 1994 से इसका वैधानिक अस्तित्व है वास्तविक रूप में वर्तमान इसके पास कोई कार्य नहीं है

प्रश्न–8 संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक व आर्थिक परिषद् के क्या कार्य हैं ?

उत्तर– यह संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है इसका कार्य विभिन्न देशों के सामाजिक विकास व आर्थिक विकास में योगदान देना है

प्रश्न–9 सचिवालय व महासचिव के बारे में टिप्पणी लिखिए ?

उत्तर– सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगो मे से एक प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसीयों द्वारा बनाये गये प्रोग्राम व नीतियों को प्रसारित एवं समन्वित करता है । इसका प्रधान महासचिव होता है तथा महासचिव की सहायता के लिए सहायक महासचिव, विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी तथा क्लर्क होते हैं।

निबंधात्मक प्रश्न

1. संयुक्त राष्ट्रसंध के संघटन पर लेख लिखिए ।

उत्तर – प्र. सं. 4 से 9 तक देखें।

मॉडल पेपर–1
विषय–राजनीति विज्ञान
(खण्ड–अ)

प्रश्न 1. नीचे दिये गये बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तरपुस्तिका में लिखिए–

(i) किस विचारक ने न्याय को एक नैतिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिवादित किया है–

(अ) अरस्तु	(ब) प्लेटो	(स) जॉन रॉल्स	(द) संत ऑगस्टाइन	(ब)

(ii) "पॉलिटिकल पार्टीज" नामक पुस्तक किसने लिखी है–

(अ) राबर्ट मिशेल्स	(ब) राबर्ट बायर्सटेड	(स) आर्गेन्सकी	(द) मैकाइवर	(अ)

(iii) 'समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती।' यह कथन किसका है–

(अ) हॉब्स	(ब) पोलार्ड	(स) महात्मा गाँधी	(द) रूसो	(द)

(iv) वन महोत्सव दिवस मनाय जाता है –

(अ) 5 जून	(ब) 22 मार्च	(स) 28 जुलाई	(द) 22 अप्रैल	(स)

(v) वित्तीय संकट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है –

(अ) अनु. 352	(ब) अनु. 356	(स) अनु. 360	(द) अनु. 362	(स)

(vi) राज्य सूची में कितने विषय हैं–

(अ) 47	(ब) 99	(स) 66	(द) 50	(स)

(vii) धन विधेयक को संविधान के किस अनु. में परिभाषित किया गया है–

(अ) अनु. 109	(ब) अनु. 110	(स) अनु. 111	(द) अनु. 112	(ब)

(viii) मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है–

(अ) राष्ट्रपति	(ब) प्रधानमंत्री	(स) उपराष्ट्रपति	(द) राज्यपाल	(अ)

(ix) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं–

(अ) 21	(ब) 20	(स) 15	(द) 24	(स)

प्रश्न संख्या 02 से 08 तक के उत्तर एक शब्द /एक पंक्ति में दें।

प्रश्न 2. वैश्वीकरण का अर्थ क्या है ?

प्रश्न 3. उपयोगितावाद का सूत्र क्या है ?

प्रश्न 4. 'पॉलिटिकल सोशलाइजेशन' पुस्तक के लेखक कौन है?

प्रश्न 5. भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है?

प्रश्न 6. किस देश में जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को "वापिस बुलाने का अधिकार" है?

प्रश्न 7. संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता हैं?

प्रश्न 8. भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश है?

प्रश्न संख्या 09 से 11 तक दिये गये रिक्त स्थानों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए।

प्रश्न 9. भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ .... को प्रदान की गई है।

प्रश्न 10. महासभा की बैठक सितम्बर के .... को नियमित रूप से होती है।

प्रश्न 11. वर्तमान में नीति आयोग के .... पूर्णकालिक सदस्य है।

शेखावाटी मिशन–100

(खण्ड–ब)

प्रश्न 12. वैधता प्राप्ति के दो साधन कौनसे हो सकते हैं ?

प्रश्न 13. स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दो शर्ते कौन–कौन सी हैं ?

प्रश्न 14. राजनीतिक संस्कृति की कोई दो विशेषताएँ लिखिए?

प्रश्न 15. परिवर्तनकारी आन्दोलन के दो उदाहरण लिखिए?

प्रश्न 16. समाजवाद से क्या अभिप्राय है?

प्रश्न 17. गणपूर्ति (कोरम) से आप क्या समझते हैं ?

प्रश्न 18. साम्प्रदायिक समस्या के कोई दो कारण बाताइये?

प्रश्न 19. भ्रष्टाचार से क्या तात्पर्य है?

(खण्ड – स)

प्रश्न 20. स्वतंत्रता के दो नकारात्मक और दो सकारात्मक पक्ष लिखिए?

अथवा

'परम्परागत रूप में न्याय की दो धारणाऐं प्रचलित रहीं हैं – नैतिक और कानूनी, किन्तु वर्तमान में सामाजिक व आर्थिक न्याय की धारणा भी महत्वपूर्ण हो गयी है।' स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 21. आमण्ड नें राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। स्पष्ट कीजिए।

अथवा

नीति आयोग के कोई चार उद्देश्य लिखिए।

प्रश्न 22. "भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को कई रूपों में देख सकते हैं।" स्पष्ट कीजिए। (कोई चार)

अथवा

"साम्प्रदायिकता के कारण ना सिर्फ राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को खतरा पैदा हुआ है बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरूद्ध हुई है" साम्प्रदायिकता के कारण उत्पन्न कोई चार दुष्परिणाम बताइए।

प्रश्न 23. भारतीय गठबंधन की राजनीति के कोई चार विशेषताऐं बताईए?

अथवा

राजनीति के अपराधीकरण के आधार पर भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य कैसा है ? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 24. न्यायापलिका द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये है। किन्हीं पाँच निर्देशों का उल्लेख करें।

अथवा

प्रश्न 25. भारतीय संविधान की विशेषताएँ बताइयें।

अथवा

भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुये भी इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 26. भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं ? बताइये।

अथवा

संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन समझाइये।

प्रश्न 27. "न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएँ एक–दूसरी से जुड़ी हैं।" सिद्ध कीजिए।

अथवा

भारतीय संसद के गठन व संरचना को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 28. भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के क्या कारण रहें हैं और वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की क्या प्रासंगिकता रही है। समझाइये।

अथवा

नियोजन क्या है ? नियोजन की आवश्यकता और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।

शेखावाटी मिशन–100

मॉडल प्रश्न पत्र–2
राजनीति विज्ञान
खण्ड (अ)

प्रश्न 1. न्याय की निष्पक्षता को राजव्यवस्था की आधारभूत प्रवृति किसने माना –

(अ) प्लेटो (ब) बृहस्पति (स) मनु व कौटिल्य (द) आचार्य नरेन्द्र देव (स)

प्रश्न 2. लैटिन भाषा के शब्द "लेजिटीमश" का अर्थ है –

(अ) हार्मफुल (ब) अथॉरिटी (स) पावरफुल (द) लॉफुल (द)

प्रश्न 3. सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौनसा युग्म सही है–

(i) व्यक्ति को विकास के समान अवसर। (ii) बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण।

(iii) समाज के सभी नागरिकों की समान आय। (iv) जातीय आधार पर भेदभावों की समाप्ति।

(अ) ii, iii, iv (ब) i, ii, iii (स) i, ii, iv (द) i, iii, iv (स)

प्रश्न 4. कौनसा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है–

(अ) असाक्षरता (ब) अराजकता का सम्राज्य

(स) कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता (द) विधि का शासन (द)

प्रश्न 5. किस देश के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है –

(अ) भारत (ब) पाकिस्तान (स) श्रीलंका (द) अफगानिस्तान (अ)

प्रश्न 6. राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं–

(अ) 15 (ब) 250 (स) 10 (द) 25 (स)

प्रश्न 7. राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं–

(अ) 35 (ब) 25 (स) 200 (द) 10 (ब)

प्रश्न 8. विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में हुई–

(अ) भादरा (ब) दांतारामगढ़ (स) खेजड़ली (द) बनेड़ा (स)

प्रश्न 9. महिलाओं को आरक्षण किस स्तर पर प्राप्त हो चुका हैं ?

(अ) पंचायत तथा नगरपालिका (ब) जिला स्तर पर

(स) राष्ट्रीय स्तर पर (द) विधानसभा (अ)

प्रश्न 10. नीति आयोग का गठन कब हुआ ?

(अ) 1 अप्रैल 2015 (ब) 1 जनवरी 2015 (स) 1 मई 2015 (द) 1 जून 2015 (ब)

प्रश्न संख्या 2 से 11 तक के उत्तर एक शब्द/एक पंक्ति में दीजिए।

प्रश्न 2. "अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" को ही न्याय का मूल मंत्र किसने माना है ?

उत्तर :– जेरेमी बेंथम ने।

प्रश्न 3. समानता को न्याय का मौलिक तत्व कौन मानते हैं ?

उत्तर :– थॉमस एक्वीनास।

प्रश्न 4. यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना जाता हैं ?

उत्तर :– मैकियावली।

शेखावाटी मिशन–100

प्रश्न 5. "द वेब ऑफ गवर्नमेंट" पुस्तक के लेखक कौन हैं ?

उत्तर :– मेकाइवर।

प्रश्न 6. "स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है" यह कथन किसका हैं ?

उत्तर :– पोलार्ड का।

प्रश्न 7. उसूली फासले का सिद्धान्त किसने दिया ?

उत्त्र :– राजीव भार्गव ने।

प्रश्न 8. राजनीतिक संस्कृति को "पर्यावरण" की संज्ञा किसने कहा हैं ?

उत्तर :– डेविड ईस्टन ने।

प्रश्न 9. WTO का पूरा नाम क्या हैं ?

उत्तर :– विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)

प्रश्न 10. वर्तमान में संविधान में मूल कर्त्तव्यों की संख्या कितनी है ?

उत्तर :– 11 कर्त्तव्य।

प्रश्न 11. वर्तमान में कौनसी लोकसभा चल रही है ?

उत्तर :– 17 वीं लोकसभा।

खण्ड (ब)

प्रश्न 12. शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएं हैं ?

प्रश्न 13. आर्थिक समानता का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 14. राजनीतिक सामाजीकरण के दो प्रमुख कार्य बताइये।

प्रश्न 15. "प्रत्याह्वान" से आप क्या समझते हैं ?

प्रश्न 16. प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है, कैसे ?

प्रश्न 17. "परिसीमन आयोग" से क्या है ?

प्रश्न 18 न्यायिक पुनरावलोकन से क्या आशय है ?

प्रश्न 19. न्यास परिषद् के दो कार्य बताइए।

खण्ड (स)

प्रश्न 20. स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली किन्हीं चार बाधाओं को सोदाहरण बताइये।

अथवा

न्याय के निम्न रूपों की विवेचना कीजिये–

(अ) सामाजिक न्याय (ब) राजनीतिक न्याय

प्रश्न 21. राजनीतिक समाजीकरण के किन्हीं चार साधनों का वर्णन कीजिए।

अथवा

आमण्ड के राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर प्रतिपादित राजनीतिक संस्कृति के किन्हीं चार प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 22. भारतीय राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की तुलना कीजिए।

अथवा

आपके दृष्टिकोण में "साम्प्रदायिकता केवल हमारे देष के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है", कैसे ? इसे दूर करने हेतु चार उपाय सुझाइये।

प्रश्न 23. भ्रष्टाचार रोकने के कोई चार उपाय बताइये।

अथवा

"गठबंधन की राजनीति" के कोई चार नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए।

शेखावाटी मिशन–100

खण्ड (द)

प्रश्न 24. "पर्यावरण जागरूकता" संबंधी महत्वपूर्ण दिवस को सुमेलित कर तालिका बनाइये–

1. वन महोत्सव	1. 22 मार्च
2. विश्व जल दिवस	2. 5 जून
3. विश्व पर्यावरण दिवस	3. 28 जुलाई
4. विश्व ओजोन दिवस	4. 22 अप्रैल
5. पृथ्वी दिवस	5. 16 सितम्बर

अथवा

संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 "पेरिस समझौते" की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न 25. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

अथवा

भारत के संविधान की प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 26. भारतीय संसद के गठन व संरचना को स्पष्ट कीजिए।

अथवा

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न 27. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के गठन एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

अथवा

सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में नव सामाजिक आंदोलन के श्रेणी विभाजन का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 28. भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना, शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक

1. रिपब्लिक – प्लेटो
2. द सिटी ऑफ गॉड – संत ऑगस्टाइन
3. ए थ्योरी ऑफ जस्टिस – जॉन रॉल्स
4. लेवियाथन – टॉमस हॉब्स
5. राजनीति : कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है– लासवेल (पॉलिटिक्स : हू गेट्स, व्हाट, व्हेन, हाउ)
6. द वैब ऑफ गवर्नमेंट – मेकाइवर
7. द माइण्ड एंड सोसाइटी – विल्फ्रेड पेरेटो
8. द रूलिंग क्लास – गीतानो मोस्का
9. पॉलिटिकल पार्टीज – राबर्ट मिशेल्स
10. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन – हरबर्ट साइमन
11. आधुनिक राजनीति और सरकार – एलन बॉल (मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट)
12. द सिविक कल्चर : पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशन्स – ग्रेब्रियल आमण्ड व सिडनी वर्बा
13. प्लान्ड इकोनोमी फॉर इंडिया – एम. विश्वैश्वरैया
14. ए थ्योरी ऑफ कॉन्फलिक्ट – बी क्रोजियर

शेखावाटी मिशन–100

प्रमुख कथन

1. "आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है, रंगमंच खून से तर–बतर है और चरित्र मृत्यु है।"– यूरी त्रिफोनाव

2. हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ हैं, इसका परिणाम है और इसका अंत है। – डेविड फ्रॉमकिन

3. आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखे और सारे लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। – ब्रेनाजिन किंस

4. संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पंहुचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। – डेग हैमरसोल्ड

5. हथियारों की लड़ाई से बेहतर है जुबानी जंग। एक ऐसा विश्व मंच बने जहाँ दुनिया के सारे देश एकत्रित हो और एक–दूसरे का सिर खाएं न कि सिर कलम करें। – चर्चिल

शेखावाटी मिशन–100

ALLEN CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)
path to success
SIKAR, RAJASTHAN

सपने होंगे सच

Pre-Nurture & Career Foundation Division

Class 6th to 10th | NTSE | OLYMPIADS & BOARD

Admission Open

Session 2021-22

New Batches for

Class 6th to 10th

7 April & 12 May 2021

(*ENGLISH MEDIUM*)

Strong Foundation Leads to

EXTRAORDINARY RESULTS

ALLEN SIKAR
Classroom Students
Qualified for

INMO
Indian National Mathematical Olympiad

&

INJSO
Indian National Junior Science Olympiad

(Conducted by HBCSE)

KRISH GUPTA
Class: 10th

DINESH BENIWAL
Class: 10th

HIMANSHU THALOR
Class: 9th

ALLEN® SIKAR Result : JEE (Adv.) 2020

प्रथम वर्ष में ही JEE (Adv.) का सर्वश्रेष्ठ परिणाम

AIR **736**

AIR **836**

SUBHASH
Classroom Student

KULDEEP SINGH CHOUHAN
Classroom Student

ALLEN® SIKAR Result : JEE (Main) 2021 (Feb. Attempt)

दो साल बेमिसाल

एलन सीकर ने गढ़े कीर्तिमान,
जेईई-मेन में दिए
शेखावाटी टॉपर्स

MATHEMATICS
100
PERCENTILE

शेखावाटी टॉपर

शेखावाटी गर्ल्स टॉपर

ROHIT KUMAR
Classroom
99.9892474 %tile

SAKSHI GUPTA
Classroom
99.8925637 %tile

ALLEN® SIKAR Result : NEET (UG) 2020

प्रथम वर्ष में एलन सीकर, क्लासरूम के 165 + विद्यार्थियों को मिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश

680/720
AIR 695
AIIMS Jodhpur

675/720
AIR 866
AIIMS Jodhpur

LAVPREET KAUR GILL
Classroom Student

AYUSH SHARMA
Classroom Student

SARVANISHTHA | RAHUL BHINCHAR | JITENDRA P.S. RATHORE | AYUSH CHOUDHARY | RAVEENA CHOUDHARY | AAKANKSHA CHAUDHARY | RAMPRATAP CHOUDHARY

PRACHI RAJPUROHIT | NIKITA | DAYANAND JYANI | ANNU | DEEPIKA GOENKA | OM PRAKASH JAT | PRAVEEN KUMAR YADAV

ADITI | MANASVI JANGIR | SANJAY SAIN | SUMIT CHOUDHARY | ANKIT | HEMANT DHAYAL

UPCOMING NEW BATCHES for JEE (Main+Adv.) & NEET (UG)

(Hindi & English Medium)

NURTURE BATCH	ENTHUSIAST BATCH	LEADER BATCH
(For Class 10th to 11th Moving Students) Starting from	(For Class 11th to 12th Moving Students) Starting from	(For Class 12th Appeared / Pass Students) Starting from
2, 9, 16 June & 30 June 2021	**7 April 2021** Both 11th & 12th syllabus will be covered	**2 June & 16 June 2021**

ALLEN® SIKAR

TEAM **ALLEN** @ SIKAR

एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट (ASAT)

04, 11, 25 अप्रैल 2021 | 09, 23, 30 मई 2021,
06, 13, 20, 27 जून 2021

90% तक स्कॉलरशिप

ALLEN® CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)
path to success

DOWNLOAD FREE SAMPLE PAPERS

ALLEN Sikar Center: "SANSKAR," Near Piprali Circle, Sikar-Jhunjhunu Bypass, Piprali Road, Samrathpura, Sikar
Tel.: 01572-262400 | **E-mail** : sikar@allen.ac.in

Corporate Office : "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Raj.) INDIA, 324005
Tel.: 0744-2757575 | **Email**: info@allen.ac.in | **Web**: www.allen.ac.in

ALLEN Info & Admission App
Download from Google play

www.allen.ac.in/sikar | facebook.com/allensikar | twitter.com/allensikar | youtube.com/allencareerinstitute